www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 41 गोरखपुर, 27 अप्रैल 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

आतंकवाद और अराजकता का समाज में कोई स्थान नहीं: योगी

लखीमपुर खीरी। जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया और कहा कि 'ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं।' लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद और अराजकता का समाज में कोई स्थान नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हमारे समाज में आतंकवाद या अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार का सुरक्षा, सेवा और सुशासन का मॉडल विकास पर आधारित है। यह गरीबों के कल्याण और सभी की सुरक्षा पर आधारित है। हालांकि, अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की हिम्मत करता है, तो न्यू इंडिया जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति का पालन करते हुए, उसे



उसकी समझ में आने वाली भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। यह नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं।

इससे पहले दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तटीकरण कार्य का निरीक्षण किया। 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की, जो हमले में अपनी जान गंवाने वाले 26 निर्दोष पीड़ितों में से एक था। अपनी निंदा व्यक्त करते हुए आदित्यनाथ ने हमले को कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम योगी ने कहा, "22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कानपुर का एक व्यक्ति मारा गया था। शुभम द्विवेदी की दो महीने पहले ही शादी हुई थी और वह वहां आतंकी हमले में मारा गया। यह आतंकियों द्वारा किया गया बहुत ही कायराना हमला है और यह दशार्ता है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसों पर है। भारत जैसे देश में इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार की कार्रवाई आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है।" उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हमले से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर चुके हैं और आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे।

भारत विरोधी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 11 गिरफ्तार

गुआहाटी। असम पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारत विरोधी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में असम के विभिन्न जिलों के कई लोग शामिल हैं और उनमें से एक ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम भी हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। सरमा ने चेतावनी दी कि और भी गिरफ्तारियाँ होंगी क्योंकि अधिकारी पहलगाम हमले से जुड़े भड़काऊ पोस्ट के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखना जारी रखेंगे।



सरमा ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समानता नहीं है। दोनों देश दुश्मन राष्ट्र हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषक मुक्ति संग्राम समिति के एक नेता को शुक्रवार को उसकी भारत विरोधी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी ऐसा रुख अपनाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन पर रासुका के प्रावधान लगाएंगे। हम सभी (सोशल मीडिया) पोस्ट की समीक्षा कर रहे हैं और हमें जो भी राष्ट्र विरोधी लगता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शुक्रवार रात श्रीभूमि जिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था।

सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि कछार जिले में इसी तरह के आरोपों में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ह्यह्यकछार पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि ह्यऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अमीनुल इस्लाम सहित दो लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया जबकि शुक्रवार को राज्यभर में छह और गिरफ्तारियां की गईं। उन्होंने गत शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, असम ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो पहलगाम में हुए जघन्य हमले के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन और बचाव करता है। शर्मा ने बताया कि पहले पकड़े गए लोगों में से दो कछार जिले के सिलचर से तथा एक-एक हैलाकांडी, मोरीगांव, नगांव, शिवसागर, बारपेटा और विश्वनाथ से है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

पाक की नापक हरकतें जारी, भारत में मौजूद पाक नागरिकों का वीजा रद्द

नई दिल्ली। पहलगाम की बैसरन घाटी में मासूम पर्यटकों का नरसंहार करने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत लगातार की जा रही है। पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की ओर से 25 और 26 की दरम्यानी रात में फिर से सीजफायर उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई. इंडियन आर्मी ने एलओसी पर पाकिस्तानियों को ऐसा जवाब दिया कि सब के सब डर से अपने बिल में जा छुपे। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर कई पोस्ट से फायरिंग शुरू की थी। फायरिंग के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक दिन पहले भी पाक ने फायरिंग की थी। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से तकरीबन 600 राउंड फायर किए थे। जवाब में भारतीय सेना ने 1300 राउंड फायर कर पाक फौज का मुंह बंद कर दिया। बारामूला के टूटमारी गली सेक्टर में पाक सेना ने फायरिंग की थी। इसके अलावा पाकिस्तान फौज ने पीओके में भी कई जगह फायरिंग की थी।

उधर, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 20 साल के सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने का प्रयास करते हुए अपनी जान गंवा दी। युवक के बलिदान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उसके परिवार से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी।

सहायता राशि का चेक शिवसेना कार्यकर्ताओं और सीमा अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों को दिया। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सैयद के परिवार से बातचीत की और हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए सांत्वना दी। पहलगाम में पर्यटकों को घुड़-सवारी कराकर आजीविका चलाने वाले सैयद आदिल ने हमले के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। जब आतंकवादियों ने गोलीबारी की तो सैयद ने अपने साथ यात्रा कर रहे एक पर्यटक को बचाने के लिए एक आतंकवादी का हथियार छीनने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान उन्हें गोली लग गई थी।

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना और नया वीजा नहीं जारी करना शामिल है।

इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र के फैसले का सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए हैं, जो 27 अप्रैल से प्रभावी होंगे. मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ह्यएक्सह्न पर लिखा, ह्यदिल्ली सरकार इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। उल्लंघन पर पूरी ईमानदारी से नजर रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

खुफिया एजेंसियों ने जारी की स्थानीय आतंकियों की सूची

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में गत दिनों 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा लगातार जारी है। हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में अब तक पांच आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अब खुफिया एजेंसियों ने जेएंडके में एक्टिव 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की है। मतलब साफ है कि घाटी में आतंकियों के सफाये का मिशन। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

पाकिस्तानी दहशतगर्दों की करते हैं मदद

सूची में शामिल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार के तौर पर जेएंडके में सक्रिय तौर पर काम करते हैं। ये पाकिस्तानी आतंकियों की सपोर्ट व उन्हें लॉजिस्टिक मदद देते हैं। साथ ही उन्हें रसद व अन्य जरूरत की चीजों के अलावा उनके रहने का बंदोबस्त भी करते हैं। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कश्मीर में अभियान शुरू किया है और वे आतंकियों के सफाये तक पीछे नहीं मुड़ने वाले हैं।

सबसे पहले स्थानीय आतंकियों का सफाया

देश के 5 दुश्मनों के घर जमींदोज करने के बाद अब सूची में शामिल 14 की तेजी से तलाश शुरू किए जाने की तैयारी है। सूत्रों का मानना है कि सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में एक्टिव स्थानीय आतंकियों का सफाया किया जाएगा। इनके घरों को भी जमींदोज किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि घाटी में कोई भी आतंकी किसी सूरत में बच नहीं पाएगा। आतंकियों को या तो खत्म कर दिया जाएगा या उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा।

निशाने पर ये 14 आतंकी

आसिफ अहमद कंडे। शोपियां का यह आतंकी जुलाई-2015 में हिजबुल मुजाहिद्दीन के संगठन में शामिल हुआ और वर्तमान में पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार के रूप में घाटी में एक्टिव टेररिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। आसिफ अहमद शेख, जैश-ए-मोहम्मद (खीट) से जुड़ा है। 2022 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल यह दहशतगर्द अवंतीपुरा का जिला कमांडर है। एहसान अहमद शेख नाम का लश्कर-ए- तैयबा का यह आतंकी पुलवामा में सक्रिय है। यह 2023 से लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है।

हरीश नजीर नाम का लश्कर में एक्टिव यह आतंकी पुलवामा का है। लश्कर का आतंकी आदिल रहमान देंतू सोपोर का जिला कमांडर है और वर्ष 2021 से यह आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी आमिर नाजिर वानी भी पुलवामा में सक्रिय है। यावर अहमद भट्ट भी पुलवामा में एक्टिव है जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है। अदनान सफी डार शोपियां जिले का सक्रिय आतंकी है। यह 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ और लश्कर व टीआरएफ के साथ सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। ये पाकिस्तानी आकाओं की सूचना आतंकयों तक पहुंचाने का काम करता है।

हारून रशीद गनी अनंतनाग जिले का हिजबुल मुजाहिद्दीन का सक्रिय आतंकी है। कुछ वर्ष पहले यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) भी गया था। वहां इसको ट्रेनिंग दी गई है। टीआरएफ और लश्कर का बड़ा आतंकी शाहिद अहमद कुटे शोपियां में सक्रिय है। वर्ष 2023 से यह इस इलाके में एक्टिव है। टीआरएफ और लश्कर से जुड़ा आमिर अहमद डार 2023 से शोपियां में सक्रिय हैं। यह विदेशी आतंकियों का मददगार है।

लश्कर में शामिल जुबेर अहमद गनी कुलगाम का बड़ा दहशतगर्द है। यह लगातार सुरक्षा बलों व टारगेटेड किलिंग में संलिप्त रहता है। हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकी जुबेर अहमद वानी अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है। 2018 से एक्टिव यह दहशतगर्द आतंकियों के मददगार के तौर पर बड़ा काम करता है।

कई बार सुरक्षा बलों पर हमले में भी इसका नाम सामने आ चुका है। शोपियां में लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त नसीर अहमद वानी लश्कर का सक्रिय आतंकी है। यह पाकिस्तानी आतंकियों की बड़ी मदद करता है।

मौजूदा संघर्ष धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन से परे : मोहन भागवत

पुणे। पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा संघर्ष धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन से परे है। उन्होंने इस संघर्ष को 'धर्म' और 'अधर्म' के बीच संघर्ष बताया, उनके अनुसार यह संघर्ष केवल धार्मिक मतभेदों पर आधारित नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़ी नैतिक लड़ाई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है। लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे, तो इसके बारे में क्या करें?



मोहन भागवत ने कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है। गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। हम अपने पड़ोसियों का कभी अपमान या नुकसान नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई पर उतर आए तो दूसरा विकल्प क्या है?

राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि एक हिंदू कभी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। उन्होंने सरकार से पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया, जिसमें 26 लोग, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, बंदूकधारियों द्वारा मारे गए थे। आरएसएस प्रमुख ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उन्हें मार दिया गया। हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे।

भागवत ने कहा कि अभी जो लड़ाई चल रही है, वह संप्रदाय और धर्म के बीच नहीं है। इसका आधार संप्रदाय और धर्म है, बल्कि यह लड़ाई 'धर्म' और 'अधर्म' के बीच है।

हमारे सैनिकों या हमारे लोगों ने कभी किसी को उसका धर्म पूछकर नहीं मारा। जो कट्टरपंथी लोगों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे।

इसलिए देश को मजबूत होना चाहिए। सभी दुखी हैं, हमारे दिलों में गुस्सा है जैसा कि होना चाहिए, क्यों-कि राक्षसों का नाश करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं, और उनमें अब किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता।

पहलगाम हमला: भारत के सपोर्ट में 15 देश लेंगे एक्शन!

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा की है।यूएन ने बात पर जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इस आतंकवाद के निंदनीय कृत्य के आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एक प्रेस बयान में 15 देशों की परिषद ने कहा कि समूह ने 22 अप्रैल को हुए जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की।

प्रेस वक्तव्य फ्रांस द्वारा जारी किया गया, जिसके पास वर्तमान में यूएनएससी की अध्यक्षता है। परिषद के अध्यक्ष फ्रांस के यूएन राजदूत जेरोम बोनाफोंट द्वारा जारी किया गया यह वक्तव्य, यू.एस. द्वारा जारी किया गया है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पीड़ितों के परिवारों और भारत और नेपाल की सरकारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की, और घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। इस बात की पुष्टि करते हुए कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है, यूएनएससी ने दोहराया कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे वह कहीं भी, कभी भी और किसी के द्वारा भी किया गया हो। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम बहुत गहरी चिंता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या महासचिव पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए रोम में हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने की योजना बना रहे हैं, तो दुजारिक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आपके साथ कुछ साझा करने को मिलेगा। दुजारिक ने इस टिप्पणी को खारिज कर दिया कि दो परमाणु देश युद्ध में जा सकते हैं।

भारतीय सेना ने किया आतंकियों के घरों को ज़मींदोज़

श्रीनगर। बीते दिनों मंगलवार 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों (आर्मी) ने आतंकियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक शामिल थे. हमले को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकी एके-47 और बॉडी कैमरा से लैस थे। उन्होंने भीड़ के बीच टारगेट कर गोलियां चलाईं।



हमले के बाद कार्रवाई के तहत अब तक लश्कर के पांच आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों (आर्मी) ने ध्वस्त कर दिया है. पुलवामा के मुर्रान इलाके में एहसान अहमद शेख के दो मंजिला घर को आईईडी से उड़ाया गया। वह जून 2023 से लश्कर का सक्रिय सदस्य था।

आर्मी ने शोपियां में आतंकी के घर को जमींदोज किया

दूसरी कार्रवाई में शोपियां जिले के चोटीपोरा में शाहिद अहमद के घर को भी विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। वह दो साल पहले लश्कर में शामिल हुआ था। इसके बाद कुलगाम के क्विमोह में जाकिर गनी के तीसरे घर को भी सुरक्षा बलों (अ१८) ने ढहा दिया। जानकारी के अनुसार, वह भी 2023 में लश्कर से जुड़ा था।

आतंकी आदिल गुरी का घर गिराया गया

सुरक्षा बलों ने बिजबेहरा इलाके में आदिल थोकर उर्फ आदिल गुरी के घर को भी विस्फोट से उड़ा दिया। आदिल पर 22 अप्रैल के हमले की योजना बनाने और पाकिस्तानी आतंकियों को मदद देने का आरोप है।

आसिफ शेख के घर पर चला बुलडोजर

त्राल में रहने वाले आतंकी आसिफ शेख के घर को भी प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। वह भी हमले में शामिल स्थानीय आतंकियों में से एक था.. इस तरह पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में लश्कर से जुड़े आतंकियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है।

▶ सेना प्रमुख का श्रीनगर दौरा, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

ऑपरेशन क्लीन की रणनीत पर काम कर रही सरकार



पहलगाम (आरएनएस)। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 अप्रैल को पहली बार कश्मीर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और सेना के अफसरों से आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली। सेना प्रमुख को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से हो रही सीजफायर उल्लंघन की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी गई। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस अब पूरे एक्शन मोड में है। कुलगाम जिले के थोकपोर्रा काइमोह इलाके में दो ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो पिस्तौल, दो मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों स्थानीय युवकों को आतंकी संगठनों में शामिल करने में सक्रिय थे। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से और बिना किसी रुकावट के की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और सरकार इसे एक चेतावनी मानते हुए ऑपरेशन क्लीन की रणनीत पर काम कर रही है।



पाक को सबक सिखाना एवं आतंकवाद को उखाड़ना होगा



पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी व्यापक स्तर पर हो रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकेगा, जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए? पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी अस्मिता पर किया गया भीषण हमला है। इस हमले के द्वारा भारत को ललकारा गया है। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना ही चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर एवं क्रूर आतंकी हमले से सारा देश गम एवं गुस्से में दिख रहा है, वहीं मोदी सरकार इस बार आर-पार के मूड में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े और कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है, जिससे वह डरा है, सहमा है, घबराया है। इन पंच शिकंजों में 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, राजनयिक मिशन की संख्या घटाई जाएगी, पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा, पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा रद्द कर दिया गया है और अटारी बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ये कदम जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति को दर्शाते हैं वहीं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का एक डिप्लोमैटिक स्ट्राइक है, जबकि भीतर-ही-भीतर किसी बड़ी कार्रवाई से इंकार नहीं किया जा सकता। सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार से अभी अधिक सख्त कार्रवाई की अपेक्षा है और आशा की जा रही है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं से भी दो कदम आगे इस बार बदला लेगी। इस बार की तांडवी टंकार एवं हुंकार पाकिस्तान की न केवल कमर तोड़ देगी, बल्कि उसके नापाक मनसूबों को हमेशा के लिये नेस्तनाबूद कर देगी। पाकिस्तान ने अब तक भारत की शांति एवं सहयोग भावना को देखा है लेकिन अब हिंसा के लिये हिंसा की खनकार देखेगा। निदोर्षों की हत्या करन वालों, विश्वसघात का मार्ग अपनाने वालों एवं निहत्थों पर कहर बरपाने वालों को अब पता लगेगा कि धर्म एवं शांतिवादियों की ताकत क्या होती है?

पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने निर्दोष पर्यटकों पर किये गये इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ली है। इस दुखद घटना ने वर्ष 2008 में दुस्साहसपूर्ण ढंग से मुंबई और भारत को हिलाकर रख देने वाले लश्कर-ए-तैयबा द्वारा रचे गए नरसंहार की याद दिला दी है। यह महज संयोग नहीं कि यह हमला 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण और पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के भारत विरोधी बयान के बाद हुआ। यह हमला पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी भूल एवं अमानवीयता एवं पाशविकता का घिनौना कृत्य बना है। मुनीर ने कश्मीर को अपने देश की ह्यगले की नसह्न बताया लेकिन यही नस अब पाकिस्तान का सर्वनाश करेगी, उसको कड़वे घुंट पीने को विवश करेगी। दाने-दाने को तरसता पाकिस्तान अब त्राहि-त्राहि करते हुए तबाही के कगार पर पहुंचेगा। एक ओर जहां बलूच विद्रोह ने मुनीर व सेना की नींद उड़ा रखी है, अब भारत उसकी नींद ही नहीं, सुख-चैन भी छीन लेगा। गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना और वह भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी.वेंस की भारत यात्रा के दौरान- यह स्पष्ट करता है कि आतंकवादियों व उनके आकाओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को चुनौती दे दी है, सीधे-सीधे ललकारा है। मोदी सरकार को सस्ते में लेने की भूल के परिणाम पाकिस्तान पहले भी भुगत चुका है, उरी (2016) और पुलवामा (2019) की तरह पहलगाम हत्याकांड में बहा निदोर्षों का रक्त व्यर्थ नहीं जायेगा। जिस तरह श्रीकृष्ण को आसुरी शक्तियों के खिलाफ महाभारत रचना पड़ा, उसी तरह मोदी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़े युद्ध की संरचना करके हमेशा के लिये आतंकवाद का सर्वनाश करे।

पहलगाम हत्याकांड के बाद न केवल समूचे देश में बल्कि कश्मीर घाटी में पहली बार गहरा आक्रोश देखने को मिला है। घाटी में 35 साल बाद पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ बंद का आयोजन किया गया है। बुधवार को बंद के आह्वान के बाद श्रीनगर में अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। लोग सड़कों में दुख और आक्रोश व्यक्त करते नजर आए और कहा कि यह घटना कश्मीर की अतिथि और शांति की भावना के साथ विश्वासघात है। यह घटना कश्मीरियों की रोजी-रोटी पर कुठाराघात है। यह कश्मीर की शांति को लीलने की कुचेष्टा है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन के इस हमले का मकसद पर्यटकों में खौफ पैदा करना और घाटी में सामान्य स्थिति की वापसी को रोकना था। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल जम्मू-कश्मीर में पैंतीस लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। लेकिन पहलगाम जैसी जगह में जहां सत्तर फीसदी लोगों की आजीविका पर्यटन से जुड़ी है, वहां स्थिति सामान्य होने में अब लंबा वक्त लगेगा। आने वाले दिनों के लिये पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव आया था। आतंकवाद लगातार सिमट रहा था, शांति का उजाला हो रहा था। वादियों की रौनक बढ़ी और बाजार गुलजार हो उठे थे। श्रीनगर के लालचौक पर मिलजुल कर त्यौहार मनाए जाने लगे थे। बागों में ट्यूलिप के फूल खिल उठे थे। बर्फ की वादियों में मंद-मंद शीतल हवाओं से चिनार के पेड़ झूमने लगे थे। जो देश एवं दुनिया के असंख्य पर्यटकों को खींच रहे थे। उम्मीदें बंध गई थीं कि एक न एक दिन आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर नई सुबह देखेगा लेकिन बढ़ते पर्यटक और मजबूत होती अर्थव्यवस्था पाक को रास नहीं आई। पहलगाम के भयावह हमले ने एक बार फिर सबको खौफजदा कर दिया। जम्मू-कश्मीर में शांति, सौहार्द और विकास पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को नागवार गुजर रहा था। इसलिए पाकिस्तान की सेना, सेना प्रमुख तौकिर मुनीर, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने मिलकर ऐसी साजिश रच डाली, जिसने उनके धर्म को धुंधलाने एवं शर्मसार करने के साथ पाकिस्तानी इरादों को भी बेनकाब कर दिया।

पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी व्यापक स्तर पर हो रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकेगा, जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए? पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी अस्मिता पर किया गया भीषण हमला है। इस हमले के द्वारा भारत को ललकारा गया है। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना ही चाहिए। यदि युद्ध अपेक्षित हो तो उसे भी अंजाम देना चाहिए। उसकी परमाणु हमले की धमकियों से आखिर कब तक डरा जायेगा? इसी के साथ इस पर भी मंथन हो कि आखिर पहलगाम में आतंकी इतनी आसानी से इतने लोगों को मारने में सफल कैसे हो गए? सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ एवं सक्रियता जारी थी। ऐसे में भारत सरकार, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए था। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कश्मीर में जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे, तब वहां जैसी चौकसी बरती जानी चाहिए थी, उसका अभाव क्यों देखने को मिला?

जिस तरह से धर्म और नाम पूछकर आतंकवादियों ने हिन्दुओं का नरसंहार किया उससे समूचा राष्ट्र आक्रोश में है। भारत की बेटी जिस की हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं हुआ था और तीन दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसकी अपने पति भारतीय नौसेना के लेफ्टीनेंट विनय नरवाल के शव के साथ तस्वीर देखकर समूचे देश का दिल दहल गया। हैदराबाद के आईबी अधिकारी मनीष रंजन को पत्नी और बच्चों के सामने मार दिया गया, ऐसे ही दर्दनाक दृश्य चारों ओर बिखरे थे। यह हमला वैसा ही जैसा हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर किया था। आज समूचा राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है। हर देशवासी चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जैसा इजराइल ने हमास को सिखाया है। बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद केंद्र सरकार ने युद्धस्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में तीव्र गर्जना करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का संकल्प व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के आगे घुटने न टेकने की बात कहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमलावरों को यथाशीघ्र कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब घाटी की उन आवाजों को भी बुलंद करना चाहिए जिन्होंने हिंसा को खारिज करके मानवता, देश की एकता एवं घाटी की शांति को चुना है।

जल्दी ठीक नहीं हो रहा बुखार, संक्रमण बना रहा बीमार

महराजगंज। इन दिनों मौसम का प्रभाव सेहत पर दिख रहा है। संक्रमण की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बुखार एक सप्ताह में नहीं ठीक हो रहा है। इसे ठीक होने में एक से डेढ़ माह लग जा रहा है।

केएमसी मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीज आ रहे हैं। मलेरिया और टायफाइड पीड़ितों में यह समस्या सामने आ रही है। इससे डॉक्टर भी परेशान हैं। लक्षण तो इन्हीं बीमारियों की तरह से दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं। इसका फायदा भी मरीजों को हो रहा है। लंबे समय तक इलाज में मरीजों की अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है।

केएमसी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बृहस्पतिवार को जाने पर इसकी जानकारी हुई। यहां ओपीडी में मरीज देख रहे फिजिशियन डॉ. मनीष ने बताया कि बीते दो माह से बुखार पीडितों की संख्या बढ़ी है। रोजाना ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही जिनको बुखार 15 दिन से अधिक आ रहा है। इनकी पूरी तरह जांच कराई गई। इसके बाद पता चला कि लक्षण तो टाइफाइड, मलेरिया की तरह दिख रहे हैं, लेकिन इसकी असल दवा काम नहीं कर रही है।

ऐसे में अनुभव के आधार पर दवाओं का संतुलन बनाकर इलाज किया जा रहा है तो इसका लाभ भी दिख रहा है। आमतौर पर बुखार एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। इस समय बुखार पीड़ितों को ठीक होने में समय लग रहा है। मेडिसिन विभाग में ऐसे मरीजों की भरमार है। औसतन एक दिन में 30 से 40 मरीज ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुखार ठीक होने में समय लगे तो विशेषज्ञ से ही इलाज कराएं, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है।

गुरुवार को केएमसी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन अनुभाग की ओपीडी में खुटहा बाजार की मंशा मिलीं। इनको बीते 10 दिन से बुखार आ रहा है। कभी ठीक हो रहा तो कभी बढ़ जा रहा है।

जिहादी आतंक का घिनौना-बर्बर चेहरा

पहलगाम में आतंकी हमले की गंभीरता इससे प्रकट होती है कि जहां गृहमंत्री अमित शाह आनन-फानन श्रीनगर के लिए रवाना हुए, वहीं सऊदी अरब गए प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प जताया कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह संकल्प तभी पूरा होगा, जब आतंकियों को शह और सहयोग देने वाले पाकिस्तान को निर्णायक रूप से सबक सिखाया जाएगा। आतंक से लड़ने का संकल्प लेने के साथ ही उसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी बनानी होती है।

कम से कम अब तो भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि आतंकियों और उन्हें पालने-पोसने वालों की कमर तोड़ने के लिए हर क्षण तत्पर रहना ही समझदारी है।

यदि पहलगाम के आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित लश्कर के मुखौटा संगठन ने न ली होती, तो भी इसमें संदेह नहीं रहता कि यह हमला पाकिस्तान के इशारे पर किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने किसी जिहादी की तरह हिंदुओं और भारत के खिलाफ अपनी घृणा का भद्दा प्रदर्शन किया था। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं



कि पाकिस्तान सुलगते बलूचिस्तान से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है और उसे यह रास नहीं आ रहा कि कश्मीर में स्थितियां तेजी से सामान्य होती जा रही हैं। भारत को पाकिस्तान के शैतानी इरादों के प्रति और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। वह न पहले भरोसे लायक था और न अब।

कश्मीर में एक बार फिर जिहादी आतंक का घिनौना-बर्बर चेहरा दिखा। आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष-निहत्थे पर्यटकों की जिस तरह पहचान पता करके गोलियां बरसाईं, उससे यही पता चलता है कि वे केवल खौफ ही नहीं पैदा करना चाहते थे, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों का खून बहाकर दुनिया का ध्यान भी खींचना चाहते थे। यह इससे साबित होता है कि उन्होंने ऐसे समय पर्यटकों को निशाना बनाया, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं और भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में। इस हमले ने यह प्रकट किया कि कश्मीर में बचे-खुचे आतंकी किसी भी सीमा तक गिरने पर आमादा हैं। आतंकियों ने उन पर्यटकों को निशाना बनाया, जो कश्मीरियों की रोजी-रोटी को ही सहारा देने कश्मीर गए थे।

उन्होंने केवल पर्यटकों की जान ही नहीं ली, बल्कि कश्मीरियों के पेट पर लात मारने का भी काम किया। इस भीषण आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटन संबंधी कारोबार करीब-करीब ठप पड़ना तय है। आखिर इतनी भयावह घटना के बाद कौन पर्यटक कश्मीर की ओर रुख करेगा?

आतंकियों ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा करने वाली घटना को अंजाम दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों और उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

सिंधु जल संधि को रोकने का मन बना रहा भारत

नई दिल्ली। भारत सरकार पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने के तरीके खोज रही है। सरकार अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने और जलविद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दे रही है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि वह दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि (आई डब्लूटी) को फिलहाल रोक रहा है।

इसके बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि इस फैसले को कैसे जल्दी से लागू किया जाए।

नदियों और बांधों से गाद निकालने का काम तुरंत शुरू किया जाएगा। इससे पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोका जा सकेगा। जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और अन्य बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पानी को जमा करने के लिए अतिरिक्त ढांचा बनाने और जलविद्युत परियोजनाओं पर काम तेज करने पर बात हुई। इससे सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत बेहतर तरीके से कर पाएगा।

नदियों और बांधों से गाद निकालने का काम सबसे पहले किया जाएगा। इससे भारत को ज्यादा पानी मिलेगा और पाकिस्तान को थोड़ा कम पानी जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में 32% की कमी का सामना कर रहा है।

तीन विकल्पों पर चर्चा हुई

बैठक के बाद पाटिल ने मीडिया को बताया, बैठक में एक योजना तैयार की गई। तीन विकल्पों पर चर्चा हुई। सरकार कम समय, मध्यम समय और लंबे समय के लिए काम कर रही है ताकि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न जाए। जल्द ही, पानी को रोकने और मोड़ने



के लिए नदियों से गाद निकाली जाएगी। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को पानी न मिले।

पानी जमा करने की कितना क्षमता है?

अभी भारत के पास पश्चिमी नदियों के पानी को जमा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। आई डब्लू टी के तहत भारत को 3.6 एमएफ पानी जमा करने की अनुमति है, लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता भी नहीं है। इसी तरह, भारत ने पश्चिमी नदियों से 20हजार मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता में से केवल 3,482 मेगावॉट क्षमता का ही इस्तेमाल किया है। अगर किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाओं पर काम तेजी से किया जाए, तो यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। सिंचाई की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस पर नीति निमार्ताओं ने ध्यान दिया है। वे चाहते हैं कि पश्चिमी नदियों के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। ऐसा तभी हो सकता है जब भारत अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाए और जम्मू-कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर पानी का प्रवाह करे। झेलम नदी पर बन रही तुलबुल परियोजना पर 1986 से काम रुका हुआ है। इस पर काम शुरू होने से मदद मिलेगी। इस परियोजना में एक बांध भी होगा, जिसमें लगभग 0.3 एमएएफ पानी जमा किया जा सकेगा। इससे इलाके में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आई डब्लू टी एक संधि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। इस संधि के तहत, पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का पानी पाकिस्तान को दिया जाना था और पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) का पानी भारत को दिया जाना था। अब भारत इस संधि पर फिर से विचार कर रहा है। टअऋका मतलब है मिलियन एकड़ फीट। यह पानी को मापने की एक इकाई है। 1 एमएएफ पानी लगभग 1233 मिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। एम डब्लू का मतलब है मेगावाट। यह बिजली को मापने की एक इकाई है।



पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च, दी श्रद्धांजलि

तुर्कपट्टी, कुशीनगर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए बृहस्पतिवार की देर रात तुर्कपट्टी बाजार में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। लोगों ने सरकार से आतंक के पर्याय और उनके आकाओं को सबक सीखने की अपील की। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा है। यह कार्यक्रम भाजयुमो जिला संयोजक शैलेंद्र कुमार तिवारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान दीपक द्विवेदी, विद्याधर ओझा, ब्यास राय, सत्यम शुक्ला, अनिल निर्मल, नागेंद्र सिंह, संतोष मद्धेशिया आदि मौजूद रहे। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए की प्रार्थना : जौरा बाजार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए फाजिलनगर ब्लॉक अंतर्गत इंटरमीडिएट कॉलेज जौरा बाजार में दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद विद्यालय में अवकाश कर दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामू चौधरी सहित पूरा स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे।

पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन

बस्ती। हरैया तहसील मुख्यालय पर विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मृतकों को श्रद्धांजलि के साथ उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलवामा हमले से हर व्यक्ति दुखी और आक्रोशित है। इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में केंद्र की सरकार को कठोर निर्णय लेने में अब संकोच नहीं करना चाहिए। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रवीण सिंह ने कहा कि इस आतंकी हमले से यह साबित हो गया है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। धर्म पूछ करके पर्यटकों की हत्या करना इस्लाामिक जिहाद का पक्का सबूत है। विश्व हिंदू परिषद के जिलामंत्री विवेक सिंह सोनू ने कहा कि अब सनातनियों को इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश मिश्र ने भी लोगों को संबोधित किया। गोरक्ष प्रांत की मातृ शक्ति की पालिका कविता त्रिपाठी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना के साथ मातृ शक्ति भी लोहा लेने को तैयार हैं। कार्यक्रम को अमित चौधरी, जय हिंद सोनी, अमित गुप्ता, कुंदन कसौधन ने भी संबोधित किया। संचालन जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र सिंह ने किया।

शिक्षकों और विद्यार्थियों ने दी श्रद्धांजलि, आतंकवाद की निंदा

गौर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के कायराना हमले से हर तरफ लोगों में गुस्सा है। बृहस्पतिवार को कृषक इंटर कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आतंकवाद की निंदा की गई। सरकार से हमले के दोषी आतंकवादियों को कठोर सजा देने की मांग की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। प्रधानाचार्य ने कहा कि जिस तरह से पर्यटकों की धर्म के आधार पर नृशंस हत्या की गई, वह निंदनीय है। इसी तारतम्यता में दुबौलिया ब्लॉक क्षेत्र के विशेषरगंज बा जार में बुधवार की देर शाम कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतकों को श्रद्धांजलि दी व सरकार से आतंकवादी संगठनों को मिटा देने की मांग की। कहा कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तानी आतंकी बौखला गए हैं। इस घटना से देशवासी दुखी हैं।



वैश्विक एकता और करुणा का प्रदर्शन करते हुए महाबोधि महाविहार में लोगों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी

अभी तो मेंहदी सूखी भी न थी: पहलगाँव की घाटी में इंसानियत की हत्या

22 अप्रैल 2025, सुबह के कुछ शांत लम्हे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाँव में बर्फीली वादियाँ पर्यटकों का स्वागत कर रही थीं। नवविवाहित जोड़े, बच्चे, बुजुर्ग झ सबको उम्मीद थी कि कश्मीर की हवा में सुकून मिलेगा, तनाव से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन तभी आतंक की आहट हुई। बंदूकें गरजीं। और उस वादी में जहाँ बर्फ गिरती है, अब खून बहा।

राजस्थान से आया एक नवविवाहित दंपत्ति भी उन्हीं पर्यटकों में था। दोनों ने अभी पांच दिन पहले ही शादी की थी। वो अपने हनीमून के लिए कश्मीर आए थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आतंकियों ने गाड़ी रोकी, नाम पूछा, पहचान की और फिर गोली मार दी। युवक हिन्दू था। बस यही उसके मरने की वजह बन गई। सिर में गोली लगी। मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी, जिसके हाथों की मेंहदी अभी भी गीली थी, स्तब्ध खड़ी थी। शोक से ज्यादा वो एक अनकहे डर में जमी हुई थी झ जैसे समय वहीं थम गया हो।



जम्मू-कश्मीर के पहलगाँव में हुए आतंकी हमले में जहाँ एक नवविवाहित हिंदू पर्यटक को उसका नाम पूछकर सिर में गोली मार दी गई। ये हमला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर की गई घृणा और आतंक का प्रतीक है। मृतक की पत्नी की स्तब्ध तस्वीर को राष्ट्र की आत्मा का जख्मी चेहरा माना गया है। यह भारत की एकता, नागरिक सुरक्षा, और धार्मिक सहिष्णुता पर चोट बताकर चेतावनी देता है कि यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो अगला शिकार कोई और होगा। यह केवल शोक प्रकट करने के बजाय जवाबदेही, निर्णायक कार्रवाई और सामाजिक चेतना की मांग करता है, ताकि आतंक के आगे इंसानियत बार-बार न मरे।

ये हत्या नहीं, धार्मिक घृणा है

यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। यह योजनाबद्ध हत्या थी -एक सोच के तहत, एक धर्म के आधार पर। आज आतंकवाद महज क्षेत्रीय या वैचारिक लड़ाई नहीं रह गया है। यह अब धार्मिक पहचान को मिटाने का एक उपकरण बन चुका है। यह हत्या बताती है कि कुछ तत्व अब यह तय कर चुके हैं कि कौन जिएगा, कौन मरेगा झ और यह फैसला नाम पूछकर किया जाएगा।

क्या यही इंसानियत है? क्या यही ह्यकश्मीरियतह्न है, जिसके नाम पर हम वर्षों से शांति की दुहाई दे रहे हैं?

जब शहीद की पत्नी की चीखें खामोश हो गईं

सोशल मीडिया पर उस पत्नी की तस्वीर वायरल हुई, जो अपने पति के शव को निहार रही थी। न चीख, न रोना, न प्रतिरोध। बस एक स्थिर मौन झ जो पूरी व्यवस्था पर सबसे कठोर आरोप बन गया। उस मौन में एक सवाल छुपा है: ह्लहमने क्या गलत किया?ह्व क्या एक जोड़े का कश्मीर आना, उसकी सुंदरता देखना, उसकी वादियों से प्यार करना अब गुनाह बन चुका है? हमें समझना होगा कि इस तस्वीर में केवल एक महिला नहीं थी, बल्कि उस पूरे राष्ट्र की आत्मा थी झ जख़्मी, असहाय और शर्मसार।

सुरक्षा की विफलता और प्रशासन की संवेदनहीनता

हर हमले के बाद सरकार की ओर से एक तैयार स्क्रिप्ट आती है - निंदा, मुआवजा, जाँच। लेकिन जवाबदेही कहीं नहीं होती। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि घाटी में आतंकियों को खुलेआम चलने-फिरने की छूट कैसे मिलती है? वे नाम पूछकर कैसे किसी को गोली मार सकते हैं और फिर बच निकलते हैं?

क्या पर्यटन सीजन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू-कश्मीर प्रशासन को यह नहीं पता कि ऐसे हमले पर्यटन, अर्थव्यवस्था और भारत की एकता झ तीनों पर हमला करते हैं?

मानवाधिकार या आतंक के अधिकार?

जब भी भारत आतंक के खिलाफ सख़्ती दिखाता है, तो मानवाधिकार की दुकानें खुल जाती हैं। दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क झ हर जगह के तथाकथित बुद्धिजीवी अचानक ह्यसंवेदनाह्न से भर जाते हैं। लेकिन जब किसी हिंदू नागरिक को सिर्फ उसके नाम के कारण सिर में गोली मारी जाती है, तब यही आवाजें खामोश हो जाती हैं। क्यों? क्या एक विशेष समुदाय के पीड़ितों के लिए ही संवेदना है? क्या हिन्दू होना अब मानवाधिकार के चश्मे से अदृश्य हो जाना है?

यह हमला पूरे भारत पर है

पहलगाँव हमला केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है झ यह भारत की आत्मा पर हमला है। यह संदेश देने की कोशिश है कि ह्लयहाँ तुम्हारी जगह नहीं हैह्व। यह भारत की एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती है। और यदि हमने इस चुनौती को केवल ट्वीट और मोमबत्तियों से उत्तर दिया, तो अगला निशाना कोई और शहर, कोई और नाम, कोई और नवविवाहित होगा।

पाकिस्तान का रोल और वैश्विक चुप्पी

हमेशा की तरह, इस हमले के पीछे जिस आतंकी संगठन का नाम आया झ ह्यद रेजिस्टेंस फ्रंटह्न झ वह लश्कर-ए-तैयबा का ही नया अवतार है। और इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अभी भी ह्यआतंकवाद का शिकार देशह्न बना बैठा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप झ सभी को यह साफ-साफ कहना चाहिए कि धार्मिक आधार पर नागरिकों की हत्या केवल एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक मानवता का संकट है।

अब निर्णय का समय है

भारत को अब दो टूक निर्णय लेने की जरूरत है। कश्मीर में आतंक का सामना केवल पुलिस नहीं कर सकती, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। अलगाववाद की नर्म परतों को उखाड़ फेंकना होगा। धार्मिक पहचान के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को सामाजिक स्तर पर भी चुनौती देनी होगी। इसके साथ-साथ, हमें यह तय करना होगा कि कश्मीर में पर्यटन केवल ह्लस्वर्गह्व दिखाने का सौदा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का सेतु है झ और इस सेतु की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है।

अंतिम पंक्तियाँ: एक और शहीद, एक और सुहाग उजड़ा

हर आतंकी हमले के बाद हम कुछ दिन दुखी होते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन उस स्त्री के लिए, जिसने अपने पति को खोया, जो लहूलुहान सपनों के साथ अकेली रह गई, यह घटना एक जीवन भर का घाव है। उसके लिए यह कोई न्यूज नहीं, यह उसका टूटता संसार है। हमारी संवेदना केवल सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें पूछना चाहिएव-कब तक? कब तक हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाएँगे? कब तक हम आतंकी हमलों पर केवल मोमबत्तियाँ जलाते रहेंगे?

डॉ सत्यवान सौरभ





पहलगाम की चीखें

जब बर्फीली घाटी में खून बहा,
तब दिल्ली में सिर्फ.ट्वीट हुआ।
गोलियाँ चलीं थी सरहद पार से,
पर बहस चली—गलती किसकी है सरकार से?
जो लड़ रहे थे जान पे खेलकर,
उनकी कुबार्नी दब गई मेल में।
और जो बैठे थे एयरकंडीशन रूम में,
लिखने लगे बयान—मोदी है कसूरवार इसमें।
कब समझोगे, ये दुश्मन बाहर है,
जो मजहब की आड़ में कत्लेआम करता है।
1400 सालों से जो आग सुलगा रहा,
उसका नाम लेने से भी डर लगता है क्या?
मोदी नहीं, वो किताबें दोषी हैं,
जो नफरत की जुबान बोलती हैं।
जो कहती हैं, 'काफि र को खत्म करो,'
और तुम कहते हो, 'सेक्युलर रहो।'
किसी ने कहा—₹पहले जाति देखो,₹
किसी ने कहा—₹धर्म ना पूछो।₹
पर जब आतंकी आया अङ-47 लिए,
उसने सीधा सीने में गोली पूछी—हिन्दू हो या नहीं?
क्या यही है तुम्हारी मानवता की परिभाषा?
क्या यही है तुम्हारी आजादी की भाषा?
जो देश के वीरों को शर्मिंदा करे,
और आतंकी सोच को गले लगाए,
वो बुद्धिजीवी नहीं, गद्दार कहे जाए।
मोदी को कोसने से पहले सोचो,
क्या तुमने भी देश के लिए कुछ किया है?
जिसने जवाब दिया बालाकोट से,
उसके इरादे पर शक करना भी गुनाह है।
पहलगाम रो रहा है, सुनो उसकी सिसकी,
ये कायरता नहीं, ये साजिश है जिसकी।
एकजुट होओ, मजहब से ऊपर उठकर,
वरना अगली चीख तुम्हारे घर से उठेगी।

प्रियंका सौरभ

दोषियों को सख्त जवाब दिया जाएगा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 121वें एपिसोड में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने देश के हर नागरिक को गहरा दुख पहुंचाया है। मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति की वापसी हो रही थी, जिसे जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों ने अपनी साजिश से बाधित करने का प्रयास किया।

'मन की बात' में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा, 'मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुँचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे ऐहसास है, हर भारतीय का खून, आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है।'

पीएम ने आगे जम्मू-कश्मीर की प्रगति के बारे में बात करते हुए कहा, 'पहलगाम में हुआ ये हमला, आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल-कॉलेजों में एक रौनक थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के माध्यम से कहा कि आतंकी और उनके आकाओं का मकसद कश्मीर को फिर से अशांत करना है, जिसके लिए वे बड़ी साजिशें रचते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है।

युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को, ये रास नहीं आया।' पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी और उनके आकाओं का मकसद कश्मीर को फिर से अशांत करना है, जिसके लिए वे बड़ी साजिशें रचते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है।

देश के लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा, 'हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है।' पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कई देशों ने देश के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने कहा, 'दुनियाभर से संवेदनाएं आ रही हैं, वैश्विक नेताओं ने मुझे फोन किया है, पत्र लिखे हैं और संदेश भेजे हैं। सभी ने इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।' पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा विश्व 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा और हमले के दोषियों को सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा।

देश के युवाओं में है असीम ऊर्जा: दयाशंकर

पकवा इनार, कुशीनगर । कुशीनगर स्थित वर्मी बुद्ध विहार के सभागार में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय युवा नेतृत्व शिविर का उद्घाटन प्रदेश के आयुष मंत्री ने किया। इसमें देश के राज्यों सहित इंडोनेशिया और नेपाल के कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुतियां देकर अखंड भारत का परिचय दिया। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि भारत नौजवानों का देश है। यहां असीम ऊजाओं का भंडार है। उन्होंने आजादी दिलाने वाले देशभक्तों के त्याग और बलिदान को याद किया। इस मौके पर असम के कलाकारों ने बिहू नृत्य, पंजाब के गिद्दा नृत्य, नेपाली नृत्य, इंडोनेशिया के कलाकारों ने योग नृत्य, पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने दुर्गा पूजा की प्रस्तुतियां, कुशीनगर की बिल्लू ने ताइक्वांडो की खूबसूरत प्रस्तुति दी। इसके पहले भिक्षु संघ अध्यक्ष एबी ज्ञानेश्वर ने बुद्ध प्रतिमा, घड़ी और इंडोनेशिया के इंद्रा उदयेना ने मुख्यअतिथि को हीलिंग बेल और नेपाल के आयुष ने नेपाली परिधान व असम के अश्वनी ने गमक्षा भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजय कुमार पांडेय ने किया। अंत में संजय राय ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया।

प्रेमचंद के सामने मानवता ही सर्वोपरि धर्म था'

उर्दू में लिखी गई ईदगाह कहानी सबसे पहले इस्मत पत्रिका के वार्षिक विशेषांक में प्रकाशित हुई। और फिर बाद में यह चांद पत्रिका के अगस्त 1933 में अंक के माध्यम से हिंदी पाठकों तक पहुंची। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं, जिनकी लेखनी हमेशा गरीबों और मजलूमों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। उनकी लेखनी के सामने कभी भी धर्म की दीवार आड़े नहीं आई। वे आपनी कृतियों में हमेशा मानवतावादी दृष्टिकोण व मूल्यों के साथ खड़े हैं और निःसंदेह मानवता ही उनके लिए सर्वोपरि धर्म था।

संत के दरगाह पर लगने वाला उर्स (वार्षिक) मेला न होता, तो अमीना और हामिद जैसे जीवंत और हृदय स्पर्शी पात्रों को जमीन कहां मिलती ? संभव है कि एका कुशल कलमकार होने के नाते प्रेमचंद को कोई दूसरा पात्र कहीं और भी मिल सकता था लेकिन क्या दरगाह, उसे अमीना और हामिद के बगैर हिंदी कहानी की यात्रा शुरू हो पाती कल्पना कीजिए कि-वर्ष 1933 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। इसके ठोस और विस्तृत साक्ष्य भले ही आसानी से उपलब्ध न हो, परंतु कुछ तथ्य अवश्य हमारी समझ को दिशा देते हैं। उदाहरणार्थ-सर्वविदित है कि 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और देश का पहला बजट मात्र आठ करोड़ रुपए का था। इन आंकड़ों से हम तत्कालीन समाज की कमजोर आर्थिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं।

ईदगाह कहानी को गहराई से पढ़ने पर यह तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। उस समय यह क्षेत्र अंग्रेजों के शासन के अधीन 'यूनाइटेड प्राविंस ऑफ आगरा एंड अवध₹ का हिस्सा था; जहां गरीबी अपने चरम भयावहता में थी। यही विषम परिस्थिति हमारे समाज की आस्था और मनोविज्ञान दोनों को आकार दे रही थी। ऐसे कठिन समय में जीवन की राह दिखाने वाले कुछ आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन भी सक्रिय थे। इनमें नाथपंथ, सूफिज्म और कबीर पंथ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। परिवर्तित संदर्भों में हमें सूफिज्म को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस सूफीवाद का प्रत्यक्ष संबंध सूफी संत मुबारक खान शहीद से जुड़ी है। सूफिज्म इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है जो आध्यात्मिकता ईश्वर के प्रति आस्था अटूटप्रेम और उसके एकाकार होने के गहन अनुभव पर बल देती है। प्रेमचंद की कालजई रचना ईद का की पृष्ठभूमि सूफी संत मुबारक खां शहीद की दरगाह पर हर साल लगने वाले मेले के जीवंत परिवेश में, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है और मेले की परंपरा भी उतनी पुरानी है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने मार्मिक कहानी 'ईदगाह' के पात्र गोरखपुर की धरती पर सूफी संत की दरगाह पर लगे मेले से साकार हुए। इस सूफिज्म की आध्यात्मिक परंपरा ने मुख्य रूप से मध्य एशिया ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से विकास किया। सूफी संत, जिन्हें पार, फकीर या दरवेश के रूप में जाना जाता है। अपनी ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति, आत्म-शुद्धि के निरंतर प्रयास और निःस्वार्थ मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में सूफीवाद का प्रभाव 12 वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के बाद और अधिक गहरा हुआ माना जाता है। चिश्ती सुहरावर्दी और अन्य सूफी सिलसिलों (आध्यात्मिक वंशों) ने यहां अपनी गहरी जड़ें जमाई हैं। सूफी संतों ने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसका प्रभाव भक्ति आंदोलन पर भी देखने को मिलता है। इन प्रमुख सूफी संतों में मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर), निजामुद्दीन औलिया (दिल्ली), बाबा फरीद (पंजाब), अमीर खुसरो और बुल्ले शाह (पंजाब) जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हैं। सूफी परंपरा का मूल सार प्रेम, करुणा और ईश्वर की निरंतर खोज है। यह आध्यात्मिक परंपरा आज भी लोगों को उन्नति सामाजिक एकता को प्रेरणा देती है।

गोरखपुर स्थित मुबारक खान शहीद की दरगाह इसी समृद्ध सूफी परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। रामगंज में नार्मल रोड के समीप स्थित यह पवित्र स्थल स्थानीय स्तर पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और यह व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। संत मुबारक खान शहीद को समर्पित यह दरगाह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केन्द्र है।जो सांप्रदायिक सदभाव की एक अटूट मिसाल पेश करती है यह पवित्र स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के असंख्य भक्तों को समान रूप से आकर्षित करता है। मुंशी प्रेमचन्द के अमर पात्र हामिद और उसकी यारी दादी अमीना आज भी कहीं न कहीं उसके जीवंत और मानवीय परिवेश में हमें मनुष्यता की सीख दे रहे हैं।

पहलगाम की गोलियाँ: धर्म पर नहीं, मानवता पर चली थीं

– प्रियंका सौरभ

कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी—यह एक ऐसा खौफनाक संदेश था जिसमें गोलियों ने धर्म की पहचान पूछकर चलना शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा, और इंकार करने पर गोली मार दी। यह न केवल एक घृणित धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र भी था, जिसका उद्देश्य कश्मीर में पुनः स्थापित होती शांति और विश्वास को तार-तार करना था।

धर्म के नाम पर किया गया अमानवीय अपराध

जब किसी को गोली मारने से पहले उसका धर्म पूछा जाता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति की जान का अपमान है, बल्कि उस पूरे समाज का अपमान है जो 'सर्व धर्म समभाव' की बात करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आतंकियों ने पहले 'हिंदू' पहचान की पुष्टि की, फिर 'गोली' को धर्म की रेखा पर खड़ा कर दिया। इससे बड़ा पाखंड क्या होगा कि किसी भी धर्म की आड़ में आतंक फैलाया जाए, जबकि हर धर्म की जड़ में 'मानवता' बसती है।

इस हमले ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी अक्सर धर्म को ढाल बनाकर उसे इस्तेमाल करते हैं। जबरन किसी से कलमा पढ़वाना और न मानने पर जान ले लेना, यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। पैगंबर मोहम्मद ने तो मक्का में भी अपने दुश्मनों को माफ किया था—यहाँ तो बेगुनाह पर्यटकों पर गोली चलाई गई।

साजिश सिर्फ जान लेने की नहीं, छवि बिगाड़ने की भी

यह हमला न केवल मानवता पर था, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी हमला था। पहलगाम, जो 'मिनी स्विटजरलैंड' के नाम से जाना जाता है, वहाँ इस तरह की घटना का होना वैश्विक स्तर पर कश्मीर को फिर एक बार 'संवेदनशील और अस्थिर' क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी—लोगों ने धीरे-धीरे डर के माहौल से बाहर निकलना शुरू किया था। लेकिन यह हमला उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश है।

पर्यटकों की वापसी का मतलब था स्थानीय लोगों की आजीविका का पुनर्जन्म। कश्मीरी दुकानदार, टैक्सी चालक, होटल कर्मचारी—सभी इस बढ़ते पर्यटन पर निर्भर थे। लेकिन अब, एक बार फिर सैकड़ों पर्यटक कश्मीर छोड़ने लगे हैं। कई बुकिंग्स रद्द हो रही हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।

राजनीति की परछाई: इस हमले के असली मकसद

'द रेजिस्टेंस फ्रंट' , जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान से संचालित हो सकता है। यदि यह सच है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि यह केवल एक धार्मिक हिंसा नहीं थी, बल्कि भारत की आंतरिक शांति को अस्थिर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश भी थी।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब भारत चुनावों की तैयारी में जुटा है। क्या यह हमला लोकतंत्र में भय और अविश्वास फैलाने की रणनीति नहीं हो सकती? क्या यह आतंकी ताकतों का एक संकेत नहीं है कि वे अब भी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भारत को अस्थिर कर सकते हैं?

पीड़िता की आँखों से देखें—राजनीति नहीं, पीड़ा दिखती है

इस हमले में मारे गए पर्यटक की पत्नी के बयान ने पूरे देश को हिला दिया—ह्लमैंने उसे मरते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी।ह्व यह वाक्य किसी भी भाषण या नारे से कहीं ज्यादा असरदार है। एक महिला की चीख, एक बच्चे का रोना, एक पर्यटक का डर—ये किसी चुनावी भाषण या न्यूज चैनल की बहस से नहीं मिटते। यह हमला न केवल गोली से मारे गए व्यक्ति का अंत था, बल्कि एक पूरे परिवार की स्थिरता का अंत था। यह उस महिला की नींद का अंत था, जो अब शायद जिंदगीभर अपने पति की लाश की छवि नहीं भूल पाएगी। और यह उस भरोसे का अंत था, जो उसने भारत की सुरक्षा पर किया था।

क्या भारत सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए?

सरकार की ओर से इस हमले की निंदा की गई और सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या निंदा पर्याप्त है? क्या हम उस स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर पाए हैं कि ऐसे हमलों को रोका जा सके? कश्मीर में बार-बार ह्यअस्थिरता के बाद स्थिरता और फिर आतंकह्न का यह चक्र कब टूटेगा?

कश्मीरी मुसलमानों की भी चुप्पी नहीं, चिंता दिखी

यह ध्यान देने योग्य है कि कश्मीरी समाज के कई मुसलमानों ने इस घटना की खुलकर निंदा की। कुछ स्थानीय व्यापारियों ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की।

इससे स्पष्ट होता है कि आतंकवाद को समर्थन स्थानीय नहीं, बाहरी है। कट्टरता कश्मीर की मिट्टी से नहीं, बाहर से आयात होती है।

अब आगे क्या?

हम सबको सोचना होगा कि ऐसे मामलों में केवल गुस्सा जाहिर करना काफी नहीं है। हमें नीतियों में बदलाव चाहिए। कश्मीर में स्थायी शांति तभी संभव है जब:

धार्मिक शिक्षा में सहिष्णुता को प्राथमिकता दी जाए।

स्थानीय युवाओं को रोजगार और भविष्य का भरोसा मिले।

कट्टरता के प्रचार पर तकनीकी सेंसरशिप लगे।

आतंकी नेटवर्क को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग किया जाए।

निष्कर्ष: यह लड़ाई धर्म की नहीं, मानवता की है

इस लेख के माध्यम से मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ—क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि किसी का धर्म पूछकर उसे मारने वालों को केवल 'आतंकी' कहकर छोड़ दें? यह समय है जब हमें मिलकर कहना होगा कि जो धर्म के नाम पर जान ले, वह किसी धर्म का अनुयायी हो ही नहीं सकता। यह हमला केवल एक पर्यटक की हत्या नहीं है, यह हमारी आत्मा पर हमला है।

हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा। हमें न केवल आतंकी संगठन ळफ्रसे सवाल करना चाहिए, बल्कि उन शक्तियों से भी जो इन्हें पनाह देती हैं, और उन राजनीतिक दलों से भी जो इस दुख का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। पहलगाम की घाटियों में बहती नदियों का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा—वहाँ अब एक सवाल तैरता है: ह्लकब तक धर्म की पहचान मौत का पैमाना बनी रहेगी?

-प्रियंका सौरभ

रेवड़ियों की राजनीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता

2023 की रिपोर्ट के अनुसार- पंजाब, राजस्थान. प. बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का कुल ऋण जी एस डीपी (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) के ५० प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है, जो चिंताजनक है। पंजाब में 2023 तक राज्य सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, जबकि राज्य की आमदनी उसका आधी नहीं थी। यह स्थिति केवल जनता को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक बोझ में धकेल देती हैं। जब सरकारें मुफ्त को घोषणाएं कर बजट का हिस्सा खर्च कर देती हैं तो, स्वास्थ्य, शिक्षा बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश कम हो जाता है। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी इस पर चिंता जताई है कि-कुछ राज्य आपने बजट का 40 प्रतिशत तक मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे है। यह राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध है और दीर्घकालिक विकास के लिए खतरनाक संकेत है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्त शेष करते हुए 2022 में कहा था कि- मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति लोकतंत्र को क्षति पहुंचा सकती है। और इसके लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि-चुनाव आयोग को इस पर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि मतदाताओं को भ्रमित करने वाली घोषणाओं पर लगाम लग सके। लेकिन चुनाव आयोग ने उसपर ठोस कार्यवाही की ही नहीं है। आयोग का तर्क है कि वह केवल आदर्श आचार संहिता को देख सकता है और वादों पर रोक लगाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

कल्याण कारी योजनाओं में लोक लुभावन वादों में फर्क किया जाना चाहिए। लंबे समय तक मुक्त बोखा न तो विकास की गारंटी है और न ही गरीबी मिटाने का तरीका। इसके साथ ही जरूरी यह कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में वित्तीय स्रोतों का उल्लेख स्पष्ट करें जिससे पता चले कि वे पैसा कहां से लाएंगे। अंततः जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि - केवल मुफ्त की योजनाएं थोड़े के लालच में वोट देना किसी भी देश की लोकतांत्रिक चेतना को कमजोर करता है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनावों के दौरान जनता को लुभाने के लिए की जाने वाली घोषणाएं अब एक परंपरा सी बन गई हैं। हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा-पत्र में मुक्त की योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं। इन सबका उद्देश्य मात्र इतना इतना मतदाताओं को प्रभावित करना और वोट बटोरना। लोकतंत्र में वादों का महत्व है। लेकिन जब ये वादे मुफ्तखोरी की संस्कृति को जन्म दे दें और सरकार की आर्थिक स्थिति पर बोझ बने तब यह चिंता का विषय बन जाता है। अगर इन योजनाओं के असर को जनता के बीच जीवन पर देखें तो यह बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है कि-गरीबों और वंचितों के लिए योजनाएं आवश्यक हैं। क्योंकि वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें राहत दे। उदाहरण के तौर पार दिल्ली सरकार बिजली और पानी पर दी गई सब्सिडी से लगभग 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले, लेकिन दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि हर-चुनाव में केवल मुफ्त की वस्तुएं देकर वोट बटोरे जाएंगे तो जनता अपनी समस्याओं को गंभीरता से समझना छोड़ देगी। कौर एक उपभोक्ता मात्र बन कर रह जाएगी। साथ ही यह आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर करती हैं। जब हर बीज सरकार से मुफ्त में मिलने लगे तो मेहनत, उद्यम और स्वयं प्रयास की भावना समाज से घटने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र के स्वास्थ, विकास के लिए खतरनाक मानी जाती है। मुफ्त योजनाओं का असर केवल समाज पर हो नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा पड़ता है किसी भी योजना के लिए बजट की आवश्यकता होती है और अगर राज्य सरकारें अपने राजस्व से अधिक मुक्त योजना कों में खर्च करेंगी तो उन्हें कार्य लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को लेकर जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुई, परंतु अब तक कोई सख्त नीति सामने नहीं आई। इसके साथ ही मुख्यधारा की मीडिया भी इस विषय पर बहुत अधिक सवाल नहीं उठती है क्योंकि मुफ्त की योजनाएं जनता के बीच लोकप्रिय होती है और विरोध करने वाले राजनीतिक जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। इस बहस का निष्कर्ष यह कि जनता को मुफ्त की चीजों की नहीं बल्कि सस्ती टिकाऊ और न्यायोचित योजनाओं की आवश्यकता।

कश्मीर में हिंदुओं को बसाने और पीओके लेने का सही समय

अब समय आ गया है जब भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी से आगे बढ़कर विपक्ष भी संसद में एकजुट होकर आतंक के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने पर अपना पूर्ण समर्थन दें। निदोषों की हत्या पर कोई भी ढुलमुल रवैया न तो देशहित में है और न ही मानवता के पक्ष में। एक सशक्त, निर्णायक और पारदर्शी नीति ही आतंक के इस घिनौने चेहरे को हमेशा के लिए मिटा सकती है।

घाटी के हालात यह है कि विगत वर्ष एक सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान और आतंकियों के लिए काम करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे सस्पेंड किया जाता है, फिर उमर अब्दुला की सरकार बनती है और थोड़े दिनों में उसे पुनः बहाल कर दिया जाता है। इक्का दुक्का बर्खास्त भी हुए मगर उन्हें जेल में नहीं डाला गया, कोई एफआईआर नहीं हुई क्योंकि पीडीपी मानती है कि घाटी का माहौल खराब नहीं दिखना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटकों के रूप में हिंदुओं की निर्मम हत्या ने यह साफ कर दिया है कि आतंक की जड़ें देश के बाहर से भीतर तक और गहरी हैं। इससे निपटने के लिए महज खोखले दावे नहीं, ठोस और निर्णायक कदमों की जरूरत है। इस घटना के बाद कश्मीर पर्यटन को भारी नुकसान होगा। लोगो में भय का माहौल बनेगा और लोग बाहरी राज्यों से यहां आने से बचेंगे जिससे स्थानीय दुकानदार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। जिस तरह से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, वह न सिर्फ कायरता की पराकाष्ठा है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती भी है। इस समय पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा। यह याद दिलाना जरूरी है कि भारत ने हर बार आतंक के खिलाफ जीत हासिल की है और इस बार भी पीछे नहीं हटेगा। हालाँकि सरकार की ओर से लंबे समय से जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है।

लगातार हो रही आतंकी घटनाएँ इस बात का सबूत हैं कि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अब समय आ गया है जब भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी से आगे बढ़कर विपक्ष भी संसद में एकजुट होकर आतंक के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने पर अपना पूर्ण समर्थन दें। निदोषों की हत्या पर कोई भी ढुलमुल रवैया न तो देशहित में है और न ही मानवता के पक्ष में। एक सशक्त, निर्णायक और पारदर्शी नीति ही आतंक के इस घिनौने चेहरे को हमेशा के लिए मिटा सकती है। जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के घाटी से विस्थापन और उसके बाद डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबाण, पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में भी इस तरह के कत्लेआम आम बात हो गई थी। कश्मीर में छत्तीस सिंह पूरा और बंधहमाहा में भी आतंकवादियों ने नरसंहार किया। तब टूरिज्म का ग्राफ तेजी से गिरा था और स्थानीय लोगो ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सैनिकों की मदद शुरू की थी। लेकिन आज जो आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदू टूरिस्ट्स को गोलियों से भूना, वह बेहद दुखद है। सूत्रों के अनुसार इसमें स्थानीय लोगो की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

आखिर कश्मीर की रोजी रोटी चलाने वाले निर्दोष टूरिस्टों ने आतंकवादियों का क्या बिगाड़ा था? वो तो न जमीन खरीदने आए थे, न कब्जा करने। कुछ घूमने आए थे और कुछ राज्य की इकोनॉमी बढ़ाने आए थे। कोई भी धर्म, कुरान, कलमा इत्यादि निहत्थे टूरिस्ट्स को मारने को नहीं कहता। यह तो महापाप है जिसके लिए आतंकियों को जहन्नुम नसीब होगी। क्या पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी और स्थानीय मददगार यह बता पाएंगे कि यह कौन सा धर्म है? मारे गए नव कपल की तस्वीर देखकर रोना आ गया था। सोचिए, ये लोग हनीमून क्यों मनाने यहां आए थे। पहलगाम में 28 टूरिस्ट्स के मारे जाने के बाद, पहली बार देश की जनता खुलकर आतंकवादियों के खिलाफ बोल रही है पर विपक्ष में छुपे कुछ गद्दार अब भी इसे राजनीतिक स्टंट कहकर अपनी ही सरकार को कटघरे में डाल रहे। निर्लज्ज भूल गए की आतंक का एक ही रहनुमा है और वह है पाकिस्तान। पहलगाम और घाटी के कई इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन तो हो रहे हैं पर आतंकी गतिविधि के समय विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई! क्यों स्थानीय भीड़ ने आतंकियों की मोब लांचिंग नहीं की! जम्मू के बाद कश्मीर घाटी में सभी विपक्षी पार्टियों ने भी घाटी बंद का आह्वान तो किया किंतु हिंदू हत्या पर एक शब्द नही बोला! घाटी में ऐसे सैकड़ों केस होते रहे। अनेक 'पूर्व' आतंकवादी सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। घोड़े वालों, टैक्सी वालों, हाउसबोट वालों, होटल का स्टाफ और वेटर में कौन आतंक और जिहाद से जुड़ा है आपको कुछ नहीं मालूम! वर्तमान राज्य सरकार भी घाटी में नए नए तरीकों से इन लोगों की जेबें भर रही है। ऐसे तत्वों को सरकारी नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी जाती हैं क्युकी ये अच्छे फंडर और वोटबैंक होते है। सिविल सर्वेंट से लेकर लोकल तक पाक परस्तों के साथ गलबहियां करते हैं। इस माहौल में मासूम हिन्दू टूरिस्ट जेब मे लाखों रु लेकर घाटी में आता है। भंयकर लूट होती है, पहलगाम जाना है और आप पठानकोट से कार लेकर श्रीनगर पहुंच गए हैं तो आप को लोकल टैक्सी लेकर ही पहलगाम के कुछ खास टूरिस्ट इलाकों तक जाना होगा। आप अपनी कार लेकर नहीं जा सकते! पिछले सीजन में घाटी के कुछ लक्जरी सूट रु एक लाख रु प्रति रात की दर पर मजबूरी का फायदा उठाकर किराये पर दिए गए। जब तक आप घाटी में अपनी जेब कटवाते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे वरना हर सीजन सैकड़ों हिन्दू टूरिस्ट घाटी में जूते चप्पल और गालियां खाकर लौटते हैं। मगर कोई इक्का दुक्का ही बताता है! हिन्दू कौम बनी ही बेइज्जत होने, जूते खाने, बलात्कार झेलने और गोली खाने के लिए ही है! खुद्दारी और आत्मस्वाभिमान सिर्फ अपने इलाके मे हैं।



पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

दुश्मन ने आज हमें फिर है ललकारा

दुश्मन ने आज हमें फिर पहलगांव से है ललकारा
घूमने गए निर्दोष लोगों को बहुत बेदर्दी से है मारा
अनजान थे सभी से किसी से न थी दुश्मनी उनकी
उन निर्दोष लोगों ने तो किसी का नहीं था कुछ बिगाड़ा
भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ हसीन पल चुराकर
जन्नत की सैर करने जा रहे गए थे घर में यह बताकर
किसे मालूम था जन्नत बन जाएगी कब्रगाह उनकी
चले गए रोता बिलखता छोड़कर सबको गम में डुबोकर
सात जन्मों का साथ निभाएंगे चले थे यह वायदा करके
जा रहे थे कहीं और किस्मत ले गई कश्मीर छल करके
सात जन्मों का साथ सात दिन में ही छोड़ कर चल दिये
अब तो जीना पड़ेगा तेरे बगैर जीवन भर यूँ ही मर मर के
रहम की भीख मांगना भी किसी काम न आई
मजहब का नाम पूछ कर सीधी गोली चलाई
देख रहा ऊपर बैठ कर तुम्हारे सब अनैतिक काम
सुहागन की लाल लाल चूड़ियां तुम्हें नजर क्यों नहीं आई
लगा दो लाशों के ढेर आज मांग रहा है हिंदुस्तान
मिटा दो इस धरा से ऐसे जालिमों के नामों निशान
क्यों पैदा किया था मैंने ऐसा जालिम बेगैरत इंसान
सोच रहा होगा आज कहीं बैठ कर भगवान
बेगुनाहों के खून से रंगे हैं जो हाथ उन हाथों को तोड़ दो
बह रही जो हवाएं दहशतगर्दी की उनका रुख मोड़ दो
पहलगांव की धरती को जिन्होंने कर दिया खून से लाल
उनकी रगों से एक एक बूंद खून की निचोड़ दो
अगर यही हाल रहा तो कश्मीर कोई नहीं जाएगा
रोजी रोटी छिन जाएगी अपने किये पर पछतायेगा
लगेगी हाय उन मासूमों की जिन्हें मौत के घाट उतार दिया
जन्नत जैसा यह गुलसितां फिर दोबारा खिल नहीं पायेगा



रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

विलुप्त जीवों के जीवन के संकेत

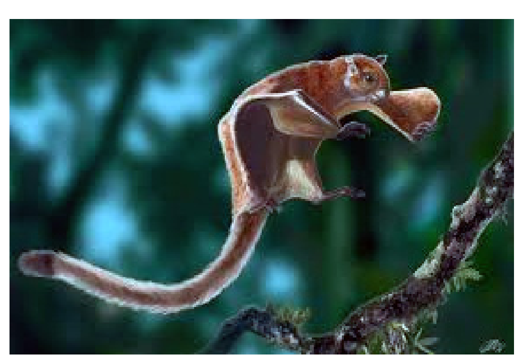
विजय गर्ग

हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ जीव-जंतुओं और जैव विविधता की महत्ता को ही भूल गए हैं या फिर जानबूझ कर भुला देते हैं? मगर जब कभी कोई अजूबा जीव-जंतु जीवित दिखा है, तो हम पुराने किस्से-कहानियों को खंगालने लगते हैं। विशेषज्ञों की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखते हैं। प्रायः ऐसे जीव दिख जाते हैं, जिन्हें हम विलुप्त मान बैठे होते हैं, लेकिन वास्तव में हैं नहीं जितना इनका मिलना विस्मयकारी है उतना ही विचारणीय भी कि वास्तव में ये दुर्लभ या मानव निर्मित कथित कृत्रिम विकास से डर कर जीवन बचाने के लिए बहुत दूर जा छिपे हैं। हम प्रकृति के उपकार को क्यों नहीं समझते?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उड़ने वाला एक जीव मिला। देश और दुनिया के वैज्ञानिक एवं जीव प्राणी विशेषज्ञ चकित रह गए। जिसे दुर्लभ प्रजाति और लगभग सात दशकों से विलुप्त मान कर 1994 से ही खोज ही बंद कर दी थी, वह अचानक जीता-जागता दिख जाए तो सबका अचरज में डूबना स्वाभाविक था। लाहौल-स्पीति में उड़ने वाली गिलहरी, जिसे 'यूपेटारस सिनेरेडस' कहते हैं, वह मानवीय गतिविधियों से मीलों दूर सुनसान इलाके में लगाए गए कैमरों में कैद हुई। यह अकस्मात ही था, क्योंकि वास्तव में सर्वेक्षण हिम तेंदुए का हो रहा था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वर्ष 2023 से बफार्नी तेंदुओं के सर्वेक्षण के लिए दुर्गम इलाकों में कैमरे लगा रखे थे, जिनमें दस अक्तूबर से चार दिसंबर 2024 के बीच हुई रिकार्डिंग को खंगालने के दौरान ऊनी गिलहरी की तस्वीरें कैद हुई।

दरअसल, वहां 'नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन' मैसूर द्वारा पिछले 15 वर्षों से शीत रेगिस्तान में दुर्लभ वन्य जीवों की खोज की जा रही थी। वास्तव में हिम तेंदुओं की जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन अन्य और विलुप्त समझे जाने वाले कुछ वन्यजीवों के अस्तित्व में होने का सच भी सामने आ गया। शीत रेगिस्तानों की जटिल और विकट भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। इससे वन्य प्राणियों उपस्थिति का वास्तविक समय, स्थान और पता करना आसान नहीं होता। शायद इसी वजह से इन्हें खोज न पाने की स्थिति में बहुत ही आसानी से दुर्लभ या विलुप्तप्रायः की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जबकि वास्तविकता इसके अलग भी हो सकती है।

हिमाचल की दुर्गम वादियों में एसपीएआइ यानी 'स्नो लेपर्ड पापुलेशन असेसमेंट इन इंडिया योजना' तहत मियार घाटी के अति दुर्गम क्षेत्रों 62 कैमरे लगाना वन विभाग और सरकारी तंत्र के लिए आसान नहीं लेकिन वहां के युवाओं के जोश ने इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस तरह वहां लगे कैमरों से हिम तेंदुओं के सर्वेक्षण के लिए तैनात दल को लाल लोमड़ी, हिमालयी भेड़िए और पहाड़ी नेवले भी दिखे। ये सभी प्राणी बफीर्ले चट्टानी इलाकों और वहां के खुले मैदानों में थे। ·· इतना तो कहा जा सकता है कि प्रकृति ने अभी अपना संतुलन काफी हद तक बनाए रखा है। जिसे हम विलुप्त समझ बैठे थे, वे मौजूद हैं।



लाहौल-स्पीति जिले में ही लगभग छह वर्ष पहले 'वैक्सविंग' नामक ऐसा दुर्लभ पक्षी मिला था जो वहां पहले कभी नहीं देखा गया। निश्चित रूप से हमने प्रकृति के विरुद्ध कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं निर्मित कर दीं, लेकिन उसने अपने अनमोल रत्नों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बचा कर रखा है। इनका मिलना बताता है कि मनुष्यों के प्रकृति विरुद्ध कृत्यों से डर कर ऐसे प्राणी कहीं दूर अपनी सुरक्षा ढूंढ़ते हुए धरती के उस आंचल में चले जाते हैं, जहां उन्हें पता होता है कि अभी इंसानों की या तो पहुंच नहीं हुई है या पहुंचना दुरूह है। हमारे लिए सुखद यह है कि अभी भी ऐसे क्षेत्र सुरक्षित बचे हुए हैं, जहां विलुप्त मान बैठे जीव-जंतु मिल रहे हैं।

विलुप्त श्रेणी में डाले गए दुर्लभ प्रजातियों के प्राणियों के मिलने से इतना तो साफ हो गया है कि पहाड़ों पर बफीर्ले, रेगिस्तानी चट्टानों और ढलानों वाले पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी मौजूदगी अब भी है और वैज्ञानिक तथा वनस्पति-प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञों को अपनी राय बदलनी होगी। साफ पता चलता है कि मियार घाटी न केवल जैविक विविधता वरन हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से अब भी कितना समृद्ध है। पर्यावरण विरोधी माहौल में ऐसे जीव जंतुओं की मौजूदगी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं इनका मिलना एक इशारा है कि अब भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। लगता नहीं कि हम सबको जैव विविधता के बारे में और भी गहराई से जानने-समझने की जरूरत है। वास्तव में यही वह तंत्र है, जिससे पृथ्वी पर जीवन है।

जैव विविधता आनुवंशिकी, प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र और कामकाज की विविधता जैसे चार हिस्सों में बांटी गई है। इन पर मंडरा रहे खतरों से सभी के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वन्यजीवों को बचाने वाली महत्त्वपूर्ण रपट इन पर आसन्न खतरों को भांपते हुए निपटने के तात्कालिक कदम उठाने के लिए सचेत कर बताती हैं कि अब भी लापरवाह रहे, तो कुछ ही दशकों में दुनिया भर में कई प्रजातियां लुप्त होंगी।

अमेरिका का ही संदर्भ लें, जिस पर आई चौंकाने वाली एक सच्चाई बेहद डरावनी है। वर्ष 1970 के बाद से उत्तरी अमेरिका से लाखों पक्षी म हो गए।। वहीं 40 वर्षों में अमेरिका में भृंगों यानी कीटों के सबसे बड़े समूह की संख्या 183 फीसद की कमी आई है। यह भी हैरान करने वाला है कि अमेरिका का 41 फीसद पारिस्थितिकी तंत्र पहले से जोखिम में हैं। समझा जा सकता कि शेष दुनिया की क्या स्थिति होगी, जिसका कोई व्यापक आंकड़ा या शोध नहीं है। वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक मंच ने पाया था कि जैव विविधता में लगातार हो रहा नुकसान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष खतरों में से एक है। अब हमें तत्काल इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना होगा।

बिगड़ते पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं के रौद्र रूप से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति के संकेत मिलते हैं, तो विलुप्त मान बैठे जीव-जंतुओं के मिलने से सुखद संदेश भी इन्हें समझने की जरूरत है। वरना जो हाल हमने अपने गांव-शहर में जल, जंगल और जमीन के साथ किया, वही यहां भी शुरू हो जाएगा तो प्रकृति की बची-खुची और एक तरह से चोरी-छिपे बचाई हुई अमानत भी वाकई विलुप्त हो जाएगी।

मलोट पंजाब

पुस्तकें भविष्य निर्माण का औजार हैं

विजय गर्ग

आज के डिजिटल युग में, जब सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स और त्वरित सूचना के स्रोत हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, ऐसे समय में किताबों की प्रासंगिकता और उनके महत्व को नए सिरे से समझना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला ह्यविश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवसह्न न केवल पुस्तकों के महत्व की याद दिलाता है, बल्कि यह दिन हमें यह सोचने को भी विवश करता है कि पुस्तकें क्यों हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए। पुस्तकों का संसार एक ऐसा अद्भुत संसार है, जो न केवल ज्ञान देता है, बल्कि भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को भी नई रोशनी प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा 1995 में शुरू किया गया यह दिवस लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों को एक साझे मंच पर लाकर पुस्तकों के संरक्षण और उनके प्रचार-प्रसार की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता को दशार्ता है। दरअसल, यह दिन विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, मिगुएल दे सर्वांतेस तथा स्पेनी लेखक इंका गार्सिलासो दे ला वेगा की पुण्यतिथि का प्रतीक है। यह दिन इस विचार से जुड़ा है कि पुस्तकें किसी देश अथवा भाषा तक सीमित न रहकर विश्व सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होती हैं। आज जब सूचना के स्रोतों की भरमार है, तब पुस्तक पढ़ने की संस्कृति तेजी से क्षीण होती जा रही है। बच्चों से लेकर युवाओं और वयस्कों तक, हर कोई डिजिटल उपकरणों से इतना जुड़ गया है कि पुस्तकों को समय देना अब एक ह्यपुरानी आदतह्न मानी जाने लगी है। विश्व पुस्तक दिवस का उद्देश्य लोगों में पुस्तकों के प्रति लगाव बढ़ाना, लेखकों और प्रकाशकों को वैश्विक सम्मान देना, कॉपीराइट जैसे संवेदनशील विषयों पर जागरूकता फैलाना और पढ़ने की आदत को जीवन का हिस्सा बनाना है। यह सर्वविदित है कि पढ़ना न केवल ज्ञानार्जन का माध्यम है, बल्कि यह ध्यान केंद्रित करने, सोचने की क्षमता बढ़ाने, कल्पनाशीलता को विकसित करने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करने में भी सहायक है। जब हम किसी पुस्तक के पन्ने पलटते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लेखक की कल्पनाओं में प्रवेश करता है, चरित्रों से जुड़ता है और किसी कथा को गहराई से समझने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की उन क्षमताओं को विकसित करती है, जो यंत्रवत सूचना को केवल ग्रहण करने से नहीं हो सकतीं। इस विषय में विभिन्न न्यूरो-साइकोलॉजिकल शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने वाले बच्चों की स्मरण-शक्ति, संज्ञानात्मक कौशल और भाषा दक्षता, उन बच्चों की तुलना में कहीं बेहतर होती है, जो अधिकांश समय स्क्रीन पर बिताते हैं। भारत में पुस्तक संस्कृति के गिरते ग्राफ को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश की बहुसंख्यक युवा आबादी की पढ़ने की आदत तेजी से घट रही है। अध्ययन बताते हैं कि औसतन एक भारतीय प्रति वर्ष केवल दो या तीन किताबें ही पढ़ता है। यह संख्या विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। हालांकि, भारत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जैसे संस्थान नियमित रूप से पुस्तक मेलों का आयोजन करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह आयोजन आम जनमानस के भीतर पुस्तकों के प्रति दीर्घकालिक लगाव उत्पन्न कर पाता है? एनबीटी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल साहित्य की बाजार हिस्सेदारी लगभग 26 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस साहित्य का ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों में व्यापक प्रसार अब भी सीमित है। बच्चों को बाल साहित्य तक पहुंचाने के लिए स्कूलों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ह्ययू डायस प्लस 2022-23ह्न रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सरकारी और निजी स्कूलों के पुस्तकालयों में प्रति छात्र औसतन 3.8 पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज जब देश शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर है, तो यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों को केवल स्क्रीन पर आश्रित न करें, बल्कि उन्हें संतुलित रूप से डिजिटल और मुद्रित सामग्री के संपर्क में लाएं। वहीं स्कूली पाठ्यक्रमों में रोचक और प्रेरणादायक साहित्य को समाविष्ट करने, स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य प्रकाशित करने और पुस्तकालयों को नवाचार केंद्र बनाने की आवश्यकता है। कॉपीराइट का मुद्दा भी इस दिवस का एक अहम पक्ष है। डिजिटल माध्यमों पर तेजी से हो रही साहित्यिक चोरी और मूल रचनाओं के अनधिकृत उपयोग ने लेखकों और प्रकाशकों को गंभीर संकट में डाल दिया है।

पुस्तकों के प्रति जागरूकता फैलाएं



प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्य में पुस्तकें हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करती हैं। जिससे कि हमारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हैं। यह हमें ज्ञान जानकारी और अनुभव प्रदान करती हैं। जो हमारे व्यक्तित्व, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक हैं। जहां एक ओर पुस्तकें बच्चों के लिए शिक्षा और ज्ञान, कलाओं, सृजनात्मकता तथा नैतिक मूल्यों का विकास करती हैं वहीं विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम की तैयारी, ज्ञान और जानकारी तथा शोध व अनुसंधान में सहायक हैं। पेशेवरों के लिए पुस्तकें ज्ञान और जानकारी के साथ-साथ उनके पेशेवर विकास तथा नेटवर्किंग और संपर्क के माध्यम से अन्य पेशेवरों से जुड़ने और नेटवर्किंग में मदद करती हैं। आम जनता के लिए पुस्तकें मनोरंजन का साधन, ज्ञान और जानकारी प्रदान करती हैं तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास के साथ ही शिक्षा और संस्कारों के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विचारशीलता को भी बढ़ावा देती हैं तथा सुसंस्कृत, नीतिवान, विचारवान नागरिकों के निर्माण में अपना योगदान देती हैं।

पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह मात्र नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र हैं जो व्यक्ति की सोच और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करता हैं। दस वर्ष पूर्व 54.6 प्रतिशत व्यस्क प्रतिवर्ष पुस्तकें पढ़ा करते थे। वहीं पांच वर्ष पूर्व 52.7 प्रतिशत तथा वर्तमान में 48.5 प्रतिशत व्यस्क लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं। एक ओर साक्षरता दर बढ़ रही हैं, नहीं दूसरी ओर पुस्तक पढ़ने की निरंतर घटती संख्या चिंताजनक हैं। अतः आवश्यक हैं कि एक जागरूकता अभियान पुस्तकों के प्रति चलाया जाए जिससे समस्त समाज को शिक्षित, सक्षम, एवं समर्थ बना सकें। एक छोटा बच्चा पुस्तक से ही आधार ज्ञान, उससे परिचय, पहचान और गिनती, साहित्य विभिन्न आकृतियों को बनाने की प्रक्रिया को सीखता हैं। पुस्तकीय अध्ययन की प्रक्रिया ही उसे डिग्री प्रदान करती है। एक चिकित्सक, वकील अन्य पेशेवर पुस्तकें पढ़ कर ही अपने गान और पेशे में वृद्धि करते हैं। यह पुस्तकें ही हैं जो लंबे सफर में हमारा मनोरंजन करती हैं। हमारे आस-पास की गतिविधियों, चरित्र निर्माण, भारती मूल्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में जानकारी देती है। ज्ञान की प्यास पुस्तकें बढ़ाती हैं और बुझाती भी। ज्ञान की दुनिया में पुस्तकें प्रवेश द्वार है।

न्यूज चैनल राष्ट्रवाद को एक स्क्रिप्टेड तमाशे की तरह पेश करते हैं। रात में टीवी पर ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया हो, लेकिन असलियत में कुछ नहीं होता। मीडिया, फिल्मों और चुनावी भाषणों में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाईयों का खूब प्रचार होता है, जबकि असली शहीदों और उनके परिवारों की पीड़ा को भुला दिया जाता है। सोशल मीडिया पर जब लोग सवाल पूछते हैं, तो उन्हें देशद्रोही कहकर चुप करा दिया जाता है। चुनावों के समय राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर असली समस्याओं जैसे बेरोजगारी और शिक्षा से ध्यान भटका दिया जाता है। यह लेख पाठकों से पूछता है – क्या वे सिर्फ इस दिखावे का हिस्सा बनकर ताली बजाते रहेंगे या असली देशभक्ति दिखाते हुए सच्चाई और पीड़ा के साथ खड़े होंगे? असली देशभक्ति शोर में नहीं, संवेदना, सच्चाई और सवाल पूछने की हिम्मत में होती है।

टीवी पर लाहौर जीत लिया, जमीन पर आँसू बहा दिए

रात का वक्त है। घरों में लोग टीवी ऑन करते हैं, न्यूज चैनल्स लगाते हैं, और अगली ही पल स्क्रीन पर धमाके शुरू हो जाते हैं – ह्लभारत ने लाहौर में घुसकर की बड़ी कार्रवाई !ह्व, ह्लपाक के होश उड़े !ह्व, ह्लघुटनों पर पाकिस्तान !ह्व जैसे शीर्षक चलते हैं और एंकर ऐसे चीखते हैं जैसे वो रणभूमि से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हों। लेकिन जब सुबह आँख खुलती है, तो सब वैसा ही होता है जैसा था। कहीं कोई युद्ध नहीं, कोई हमला नहीं, बस टीआरपी का तिलिस्मी खेल था। यह युद्ध नहीं, एक स्क्रिप्टेड शो है – राष्ट्रवाद का एक सजीव तमाशा, जो टीआरपी के नाम पर परोसा जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा, शहीदों की शहादत और जनता की भावनाएं भी अब मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा बन चुकी हैं?

मीडिया का 'वीर रस' तमाशा:

भारतीय न्यूज चैनल अब सूचना का स्रोत कम और नाटकीय मनोरंजन का मंच अधिक बन चुके हैं। एंकर युद्ध के मूड में होते हैं, पैनल में रिटायर्ड जनरल्स, कट्टर राष्ट्रवादी प्रवक्ता और एक दो रदुश्मन देशर के चेहरे बिठाए जाते हैं। सब चीखते हैं, एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, और दर्शक टीवी से चिपके रहते हैं।

सीजीआई से बना नकली बम, मिसाइल के धमाके, और नकली नक्शे – यह सब दर्शकों को एक 'महायुद्ध' का आभास कराते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि इस पूरे ड्रामे से सिर्फ एक चीज मजबूत होती है – चैनल की रेटिंग और सरकार की छवि।

सर्जिकल स्ट्राइक, सिनेमा और सेंसर:

2016 की उड़ी घटना के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अगले साल इसपर आधारित फिल्म रउरीर आई। देश ने इसे हाथोंहाथ लिया। ह्लळ्ङ्खद्धह्लर ३ँ ङ्गरँ ?ह्व डायलॉग हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। विक्की कौशल हीरो बन गए, और परेश रावल जैसे अभिनेता पर्दे पर 'रॉ' चीफ अजित डोभाल बन गए – जो हर मिशन में एक मोबाइल यूज करते और फिर फेंक देते। लेकिन इन सबके बीच असली ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सैनिक, उनके परिवार और उनकी बलिदान की कहानी कहीं खो गई। जब कोई जवान शहीद होता है, तो न्यूज चैनल पहले उसकी फोटो के साथ ब्रेकिंग चलाते हैं – ह्लएक और जवान शहीदह्व, लेकिन अगले ही पल एंकर ट्रेंडिंग टॉपिक पर लौट आता है।

सोशल मीडिया और सबूत की राजनीति:

जब बालाकोट एयरस्ट्राइक हुआ, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया – क्या सबूत हैं?, कितने मरे?।

सरकार चुप रही, लेकिन ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई। जिसने भी सवाल उठाया, वह पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। राष्ट्रवाद अब ह्यसाइलेंसिंग टूलह्ल बन गया है – जो बोलता है, वह देशद्रोही है। जो पूछता है, वह गद्दार है। जनता से जवाबदेही माँगना अब भी अपराध बना हुआ है, और सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति का मतलब बस प्रोफाइल फोटो बदलना और ट्रेंडिंग हैशटैग लगाना रह गया है।

शहीद के आँसू और आम आदमी का अकेलापन:

मीडिया युद्ध तो दिखाता है, लेकिन युद्ध में जो लोग वाकई मरते हैं, उनका क्या? जम्मू-कश्मीर या उत्तर-पूर्व में जब कोई जवान शहीद होता है, तो क्या उसकी विधवा की पेंशन समय पर आती है? क्या उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है? क्या उसकी बूढ़ी माँ को इलाज मिलता है? अक्सर नहीं। मीडिया एक दिन रोशनी डालता है, लेकिन सरकार और समाज बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो बच जाते हैं, वे अकेले रह जाते हैं। वो मां जो कहती है, मेरा बेटा तिरंगे में लिपट कर आया, मुझे गर्व है – उसे गर्व के साथ साथ जीवनभर की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है।

राजनीति और राष्ट्रवाद की साठगांठ:

चुनाव के मौसम में यह ह्यटीवी युद्धह्ल और भी आक्रामक हो जाता है। नेताओं की रैलियों में सर्जिकल स्ट्राइक का ज़िक्र होता है, बटन दबाने को ह्यबम गिरानेह्ल जैसा बताया जाता है। विपक्ष के सवाल को रपाक प्रेमर कहा जाता है, और राष्ट्रभक्ति के नाम पर असली मुद्दे – बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य – सब गायब हो जाते हैं। हर बार चुनाव के करीब कुछ न कुछ रस्ट्राइकर होता है – कभी एयर, कभी डिजिटल, कभी बयानबाजी की। देश की सुरक्षा को एक चुनावी ब्रांड बना दिया गया है। जो वोट न दिला सके, वो देशप्रेम कैसा?

जो लोग युद्ध का नारा लगाते हैं, वे कभी युद्ध नहीं लड़ते। युद्ध लड़ते हैं – वो जवान जो पहाड़ी पोस्ट पर जीरो तापमान में बैठते हैं, वो परिवार जो हर फोन कॉल से डरता है, और वो माँ जो हर दरवाजे की आहट से चौंक जाती है। और आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले आम नागरिक – उनकी भी कोई आवाज नहीं। उनके लिए कोई फिल्म नहीं बनती, कोई नेता श्रद्धांजलि नहीं देता, कोई मीडिया चैनल ब्रे-किंग नहीं चलाता।

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देशभक्ति अब एक टीवी शो बन चुकी है, फिल्मी स्क्रीन पर बिकने वाली स्क्रिप्ट है और चुनावी रैली में गूंजता हुआ नारा है। असली देशभक्ति – सवाल पूछना, पीड़ित की मदद करना, और सच्चाई को पहचानना – अब खोती जा रही है।

हमें तय करना होगा कि क्या हम इस तमाशे का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसके विरोध में खड़ा होना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ तालियाँ बजाना चाहते हैं, या शहीद के परिवार के आँसू पोछने वाले बनना चाहते हैं?

-प्रियंका सौरभ

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पाकिस्तानियों के बढ़ते मंसूबे



बांग्लादेश में तख्तापलट और वहां भारत विरोधी भावनाओं के उभार के बाद पाकिस्तान के मंसूबे और अधिक बढ़ गए हैं कि वह भारत में आतंकवाद फैलाए और आतंकियों और आतंकवाद के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करे। गौरतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है और इसका पता हमें इस बात से चलता है कि कुछ समय पूर्व अमेरिका ने आतंकी खतरों के कारण अपने नागरिकों को पकिस्तान की यात्रा न करने की एडवाइजरी भी जारी की।

हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले मे विदेशी नागरिकों समेत 26 की मौत हो गई और मरने वालों में अधिकांश पुरुष हैं। वास्तव में यह बहुत ही दुःखद और निंदनीय चला है। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब करीब सवा दो महीनों के बाद अमरनाथ यात्रा होनी है। कहना गलत नहीं होगा कि इससे आतंक का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया है। वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद बलि में सबसे घातक व बडा हमला है। हमले के बाद क्षेत्रमें आपरेशन तेजी से बलाया जा रहा है। और पर्यटकों को कश्मीर से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। सहायता के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। कितनी बड़ी बात है कि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। और गोलीबारी की। घटना के बाद अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, सऊदी अरब दौरा बीचों ही छोड़कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचते ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक की है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक बुलाई गई। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने आई बी चीफ, जम्मू-कश्मीर के डीजी और सेना व सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेबल मीटिंग भी की और पीएम मोदी इस बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से उपलब्ध रहे। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं। बताया जार है कि कुल- चार आतंकियों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया जिस में से तीन पाकिस्तानी और एक स्थानीय कश्मीरी है।

ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि यह वारदात तब हुई जब सैलानी घुड़सवारी कार रहे थे। तभी आतंकी वहां पहुंचे और उन्होंने पंजाबी भाषा में टूरिस्ट से उनका मजहब पूंछा और पहचान कायम होने के बाद लोगों को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल, आतंकी हमले के बाद सामने आए वीडियो में इस बात की पुष्टि हुई है कि हथियार बंद हमलावरों ने नाम पूंछ कर गोली मारी। जानकारी के अनुसार. इस दौरान आतंकियों द्वारा करीब 50 राउंड फायरिंग की गई है। गौरतलब है कि आतंकी सेना व पुलिस जैसी वर्दी में थे और सभी के पास एके-47 और दूसरे हथियार थे। बहरहाल यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि इसे कश्मीर घाटी में जिहादी आतंक का अत्यंत घिनौना बर्बर स्वरुप से कहा जा सकता है। वास्तव में आतंकियों ने पहलगाम में विदेशी पर्यटकों की जिस तरह पहचान करके (नाम व मजहब पूछ कर) गोलियां बरसाई उससे तो यही लगता है कि वे केवल कश्मीर घाटी में खौफ ही पैदा नहीं करना चाहते थे बल्कि बड़ी संख्या में लोगों का खून बहा कर दुनिया का ध्यान भी खींचना चाहते थे। आतंकी धर्म पूछ कर गोली मार रहे हैं और यह बात कही जाती है कि आतंकवाद और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकियों ने ऐसे समय में पर्यटकों को निशाना बनाया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में

है और भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में। यह हमला मानवता की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जो कश्मीरियों को पर्यटन के रूप में किसी न किसी रूप में सहारा देने कश्मीर गए थे। निश्चित ही इस आतंकी हमले का असर घाटी के पर्यटन व दैनिक जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि -हमले के बाद डर का माहौल घाटी में पैदा हो गया है। हमले के बाद पूरे देश आक्रोश की लहर है। वास्तव में 370 हटाए जाने के बाद इतना बड़ा हमला / आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों को करारा जवाब दिया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है। जिन आतंकियों ने हमले का अंजाम दिया है, उनमें से तीन पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत इस हमले का मुंहतोड़ करारा जवाब दे। आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाली झेल रहा है। उस पर बहुत पहले से आतंकवाद और आतंकियों का ठप्पा लग चुका है। पाकिस्तान की यह आदत रही है कि वह भारत के खिलाफ छद्मयुद्ध का खेल खेलता रहता है। एक तरफ तो वह भारत से भाईचारे और भाईचारे की बात करता नजर आता है। दूसरी तरफ आतंकवाद का घिनौना खेल खेलता रहता है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत हिन्दू धर्म, दो राष्ट्र सिद्धांत, कश्मीर और गाजा जैसे मामलों पर बयान दिए और उनके ये बयान न सिर्फ विवादित थे बल्कि विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कुछ समय पहले ही कश्मीर मुद्दे को हवा देते हुए इसे अपने देश की गले की नस बताया था और कहा कि इस्लामाबाद इसे नहीं भूलेगा। उल्लेख्य है कि पिछले वर्ष 2024 में भी जनरल मुनीर ने सेना की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन खुले आम किया जा रहा है और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। मई- 2024 में भी भारत को अपना कट्टर प्रतिद्वंद्वी बताते हुए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने - कश्मीर को इस्लामाबाद के नैतिक राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने का वादा किया था। संभव है कि- कट्टरपंथियों को जनरल मुनीर की बातों से कहीं न कहीं ताकत मिली होगी। सच तो यह है कि- जनरल मुनीर के बयानों से आतंकियों का दुःसाहस बढ़ा है और निश्चित रूपसे इसका जीता जागता प्रमाण कश्मीर की घाटी के पहलगाम में विदेशी पर्यटकों के ऊपर किया गया जान लेवा हमला है।

हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी

कश्मीर के खुबसूरत पर्यटक स्थल पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई और घायलों में से कइयों की स्थिति गम्भीर है। इस हमले की कश्मीर के वासियों ने भी निंदा की है और पूरे कश्मीर को बंद रखा। हर घटना होने के बाद जो कवायद होती है पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियों द्वारा वह जारी है। इस हमले में बताया जा रहा है कि चार से छः आतंकी थे जिसमें पाकिस्तानी और स्थानीय कश्मीर के रहने वाले आतंकी भी थे, जिन्होंने इस इस घटना को निर्ममता पूर्वक अन्जाम दिया।

इनका मकसद क्या था? निर्दोष निहत्थे पर्यटकों से इनकी क्या दुश्मनी थी? यह घटनाएं पर्यटक स्थलों पर करने का उद्देश्य निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया को यह चुनौती देने का था कि कश्मीर अभी शांत नहीं है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी घटना घटी है। पहलगाम का यह इलाका ऐसा है जहां घोड़े खच्चरों और पैदल ही जाया जा सकता है ऐसे में आतंकियों ने इसका लाभ सम्भवतः इसलिए उठा लिया क्योंकि वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या केन्द्र ने यह मान लिया था कि अनुच्छेद 370 हटाने और आतंकियों से सेना और पुलिस की मुठभेड़ों के बाद आतंकियों का सफाया हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की और करने की कोशिश की। कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी वहां केन्द्र के ही जिम्मे है। जहां पुलिस खुफिया का बहुत बड़ा जाल है। कोई भी आपरेशन त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होता है तो हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। यदि पहलगाम भी सुरक्षा व्यवस्था होती तो कम से कम इस तरह की घटना को आतंकी अंजाम नहीं दे पाते।

वास्तव में यह तो हमारी सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था की असफलता ही नजर आती है क्योंकि जब कोई बड़ा अधिकार नेता आता है तो सारी सुरक्षा व्यवस्था करके डल झील में भी कार्यक्रम करा लिया जाता है लेकिन एक आम भारतीय पर्यटक जो अपना पैसा खर्च करके अपने संसाधनों से इन स्थानों पर आता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है? इससे तो यही लगता है कि सारा ध्यान और सुरक्षा सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। आखिर ये आतंकी यदि विदेशी हैं तो यहां तक बार्डर पार करके कैसे पहुंचे और घटनाओं को अन्जाम दे सके, जब चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे अधिक सेना और पुलिस के जवान यहां तैनात हैं, पयर्टन यहां की अर्थव्यवस्था का साधन है। जिसमें हर कश्मीरी लगा हुआ रहता है। लेकिन कश्मीर में पयर्टकों की रक्षा योजना ही नहीं तैयार की गई। अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा या कश्मीर में अन्य अवसर विशेष पर होने वाली यात्राओं और समारोहों के लिए ही क्या सुरक्षा का खाका बनाया जाता है। बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए ऐसे स्थलों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यदि होती तो इतनी संख्या में न तो लोग हताहत हो पाते और न ही निर्द्वन्द होकर गोलियां चलाने की स्थिति हो सकती थी। जहां तक देश के अन्दर पर्यटन का सवाल है... कश्मीर हमेशा से लोगों के दिल में रहता है कि एक बार कश्मीर जरूर देख आयें क्योंकि कहा जाता है कि धरती में यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। यही कारण है कि जहांगीर के समय कश्मीर मुगलों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था जहांगीर और उसके बाद के मुगल शासकों ने बाग बगीचे और इमारतें बनवाई। जहांगीर ने कहा था

'गर फिरदौस बर रुए जमीं अस्तो
हमीं अस्तो, हमीं अस्तो, हमीं अस्तो।'
यानी अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है।

कश्मीर के इस स्वर्ग को आतंकियों ने लहू-लुहान करके रख दिया है। पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की घटना घटी उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास स्वचालित गन- एके 47 या एके 56 जैसी गन थी जिससे अधाधुंध गोलियां बरसायी गई और कुछ पुरुषों को अलग करके उनके नाम पूछे गए और गोली मार दी गई। पहलगाम एक घाटी और जंगल नुमा इलाका है जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए प्रतिवर्ष पर्यटक जाते हैं। सरकार कहती है कश्मीर में अब आतंकवाद समाप्त हो गया है इसलिए पर्यटक भी निश्चिन्त होकर आते हैं। उन्हें भय नहीं रहता है क्योंकि पहले आये दिन होने वाली घटनाएं सुर्खियां बनती थीं जिससे वहां आने से पहले लोग अनेक बार सोचते थे कि जाएं या न जाएं। इस कारण पयर्टकों की आवाजाही में कमी आई थी लेकिन अब लोग यह समझ रहे हैं कि वहां सब शांति है तो कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है लेकिन कश्मीर को एक प्रयोग के तौर पर समय- समय पर सरकारें अपनी रणनीति तय करती है लेकिन इस भयावह घटना से यही लगता है कि यह कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेन्सियों की पूरी तौर पर असफलता है जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके घर परिवार बिखर गए। रोते बिलखते बच्चे महिलाओं के दर्द को क्या हम बांट पायेंगे जो कश्मीर को शांत और सुरक्षित समझकर हंसी खुशी पर्यटन के लिए यहां आए थे। सरकार उन सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की असफलता माने या न माने लेकिन वह इससे मुक्त नहीं हो सकती है। हमारी कमियों और लापरवाही का ही फायदा यह आतंकी उठाते हैं।

कश्मीर में अधिकार सीएम के पास नहीं उप राज्यपाल के पास

1989 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जिस प्रकार पनपा और बढ़ा उसके बहुत से कारण विद्यमान थे जिसमें देश के अंदर से लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिकी दखलंदाजी भी शामिल रही जिससे इस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ा फला-फूला तब से अब तक सेना और पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अनगिनत आतंकी मारे गए लेकिन यह रक्तबीज बढ़ता ही गया। नए-नए नामों नाओं से आतंकी संगठन बनते गये और पहले बाहरी आतंकी और उसके बाद कश्मीर के लोगों को भी शामिल करके इस क्षेत्र को रक्तरंजित कर दिया गया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हथियार, गोला-बारूद की मदद से बाहर से की जाती रही।इसके शिकार न जाने कितने निर्दोष लोग हो गए और आज भी यही हो रहा है। आए दिन कोई न कोई टारगेट किलिंग हो रही है और उसके बाद सेना उससे दोगुना आतंकी कार्रवाई कर यह मान लिया जाता है कि इससे आतंकवाद खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में लंबे अर्से से राजनीतिक संवाद की प्रक्रिया बाधित रही है। चुनाव के बाद नेशनल कांग्रेस की सरकार

जरूर बन गई है लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सारी अधिकार उप राज्यपाल के पास है जिसे चुनाव के पहले ही अधिक ताकतवर बना दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि - जम्मू कश्मीर एक बार्डर का इलाका है। इसकी संवेदनशीलता से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में निर्वाचित सरकार को कमजोर बना कर और उप-राज्यपाल को जो केन्द्र का प्रतिनिधि है मजबूत करके हम किसी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक प्रक्रिया संवाद की भी शुरू नहीं कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की स्थिति तो राज्य दिल्ली से भी गई गुजरी है। आतंकियों ने एक बार फिर से निर्दोष लोगों पर कायराना हमला किया है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर के लोग अछूते नहीं रह सकते हैं इसका प्रभाव उन सब पर भी पड़ना स्वाभाविक है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की है।

आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ सेना और पुलिस ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हमें यह माननी पड़ेगा कि पाक प्रायोजित कस आतंकवाद में विभिन्न फिरकों से राजनीतिक संवाद की पक्रिया जम्मू-कश्मीर में आरंभ करनी होगी तभी हम बाहरी आतंकवाद से निपट सकी हैं। आतंकवाद से निबटने के लिए हमें अपनी रणनीति को बदलना होगा। क्यों कि यह गोला बारूद और हथियार से नहीं जाएगा। इसके लिए उस असंतोष को समझना पड़ेगा। उस विचार को भी कहीं न कहीं समझना पड़ेगा और जो लोग गुमराह होकर उनके साथ चले गये है उनके बारे में भी बात करनी ही पड़ेगी।

दक्षिण-कश्मीर के अनंतनाग जिले पर्यटन स्थल पहलगाम के निकट हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक पर्यटक घायल है। चश्मदीदों के अनुसार - आतंकियों ने घुड़सवारी करते हुए पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी है। इस हमले में बताया जाता है कि कुछ घोड़े भी घायल हो गए है। बहीं लश्कर ए-तैयबा से जुड़ा संगठन हो आरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत देश के प्रधान मंत्री, गृहमंत्री एवं अन्य राजनेताओं ने इस घटना की कड़ी निन्दा की है। हमला बैसरन घाटी में किया गया जहां सिर्फ पैदल या खच्चरों में छिपे हुए थे। इनमें से दो तीन हमलावर पुलिस वर्दी में थे। सुबह ही पर्यटकों का यह समूह पहलगाम गया था। हमले में दो विदेशी नागरिकों के मौत की खबर है जिसमें एक इटली और दूसरे इजरायल के बताये जा रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी श्री नगर पहुंचे। जहां उन्होंने राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की। हाल के वर्षों में पर्यटकों पर यह बहुत बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। चूंकि पर्यटकों को आमतौर पर टारगेट नहीं किया गया जाता था क्योंकि उससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। यहां होने वाली अमरनाथ की यात्रा को लेकर भी कश्मीर के लोगों की अर्थव्यवस्था जुड़ी रहती है क्योंकि यहां कारीगरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं।

केंद्र सरकार ने नोट बंदी की थी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। तब भी यही कहा था कि - इससे यहां आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसे अनुच्छेद-370 हटने के साथ ही राज्य का दर्जा घटा कर केंद्र शाशित -क्षेत्र बना दिया गया और इसे दो आगों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर एक राजा था। जो महाराजा हरि सिंह के समय पाक अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान तक फैला हुआ था लेकिन महाराजा की स्वतंत्र राज्य रखने की इच्छा और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौते के बाद मिले पाकिस्तान ने इसे धोखे से इसे कहीं का नहीं रखा। अंततः भारत को इसे बचाने के लिए आगे आना पड़ा।

भारत में अस्थिरता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता पाक

पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह भारत में अस्थिरता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता रहा है। पुलवामा हमला उसी साजिश का हिस्सा है। आतंकियों ने धार्मिक आधार पर हत्याएं करके हिन्दू मुस्लिम एकता को निशाना बनाया। हालिया दिनों में बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और पलायन की खबरों ने पहले ही सामाजिक तनाव को बढ़ाया था। ऐसे में इस (पहलगाम) के हमले ने उन भावनाओं के भड़काने का काम किया।

पाकिस्तान का मकसद साफ है। वह नहीं चाहता कि भारत में हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ जीवन बिताएं। इस हमले ने यह भी संदेश दिया है कि आतंकी संगठन अब नई रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं। टी आर एफ (द रेजिस्टेंस फोर्स) जो लश्कर-ए-तैयबा के अर्ज दर्शन में कार्यों को अंजाम देता है ये भी अपनी कार्यशैली में बदलाव किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार-वे स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। वे पढ़े-लिखे, नौकरी पेशा लोगों को पैसे और जिहाद के नाम पर बेनवाश करके अपने जाल में फंसाते हैं। ये लोग चेहरा छिपाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगले दिन अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं। ऐसी रणनीति खतरनाक है और इसे रोकना भी जरूरी है। जो एक चुनौतीपूर्ण है। इस घटना ने भी राजनीतिक परिदृश्य पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष के कुछ नेता राष्ट्रीय हितों से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं। वे हर मुद्दे को सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। विदेश यात्राओं के दौरान भी वे देश की छवि को धूमिल करने से नहीं चूकते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब देश को आतंक के खिलाफ लड़ने की जरूरत है तो कुछ नेता अपनी संकीर्ण सोच के कारण राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। एक समय था जब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि थे। जब कांग्रेस की सरकार भी और पाकिस्तान को वैश्विक में च पर जवाब देना था, तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी बाजपेयी को-चुना गया। बाजपेयी ने न सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि भारत की एकता और ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। आज के नेताओं को असे प्रेरणा लोने की जरूरत है।

भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम में आतंकियों ने धर्म की आधार बनाकर हिंदू पर्यटकों को चुन-चुन कर निशाना बनाया। इस जघन्य कुला ने न सिर्फ कश्मीर की शांति को भंग किया बल्कि पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। यह घटना तमाम सवालों को जन्म देती है जिनका जवाब देश की सुरक्षा, नीति और सामाजिक एकता के लिए अनिवार्य है। आखिर आतंकियों ने मारने वाले का धर्म क्यों पूछा, उनसे नमाज पढ्ने को क्यों कहा गया और उनकी शिनाख्त के लिए कपड़े क्यों उतारे गए। थे प्रश्न मात्र भावनात्मक, नहीं बल्कि गहरे सामरिक और सामाजिक मंथन की मांग करते हैं। पहलगाम जिसे मिनी स्विटजरलैंड के नाग से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं शांति के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है लेकिन इस बार बैसरन में जो हुआ वह मानवता को शर्मसार करने वाला था। आतंकियों ने 28 पर्यटकों को निशाना बनाया और प्रत्येक की हत्या के पहले उनके धर्म की शिनाख्त की। जबकि उनकी पत्नियों को जिंदा छोड़ दिया। एक क्रूर संदेश दिया गया जाकर मोदी को बता देना। यह संदेश न केवल भारत सरकार के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी एक चुनौती था।

आतंकियों का यह कृत्य केवल हिंसा तक सीमित नहीं था बल्कि यह हिंदु-मुस्लिम एकता को तोड़ने और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिश की इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है के आतंकियों ने धर्म के आधार पर हत्याएं क्यों कीं? नमाज पढ़ने की मांग और शारीरिक शिनाख्त जैसे कृत्य आतंकियों के नापाक मंसूबों को उजागर करते हैं। यह केवल एक आतंकी हमला नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता पर हमला था जिसका मकसद देश में अराजकता पैदा करना था। जम्मू कश्मीर से धारा 30 और 35 हटने के बाद घाटी में सकारात्मक बदलाव की लहर देखी जा रही थी। केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर में शांति विकास की नई शुरूआत हुई थी।

कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ फिर से गुलजार हो रही थी। स्थानीय लोग जो दहशत और आतंक के साये में जी रहे थे उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। महसूस कर रहे थे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने केवल उसकी आय में वृद्धि की बल्कि उनके मन में विश्वास भी जगाया कि अब कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह बदलाव पाकिस्तान और उसके पोषित आतंकियों एवं संगठनों को फूटी आँख नहीं सुहाया।

कश्मीर की शांति और स्थिरता उसके लिए खतरा बन रही थी। घाटी में आतंकियों को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। विधानसभा चुनावों में कुछ राजनीतिक दलों (नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) ने धारा 370 को फिर से लागू करने का वादा करके स्थानीय जनता को बरगलाने की कोशिश की। इन दोनों को सत्ता मिलने से केंद्र सरकार को सीधी पकड़ कमजोर हुई जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया।

पहलगाम के हमले ने एक सवाल यह भी खड़ा किया है कि- क्या यह हमला बिना स्थानीय सहयोग के संभव था। आतंकी संगठनों को स्थानीय स्तर पर समर्थन और सूचना के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना मुश्किल है। संभावना है कि कुछ स्थानीय लोग पैसे के लालच में या जिहाद के घर आतंकियों के जाल में फंस गए हों।

ऐसी घटनाएं यह दशार्ती हैं कि आतंकवादी केवल सीमा पार ही नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर भी मौजूद हैं। इन जड़ों को उखाड़ने के लिए न केवल सैन्य कार्रवाई, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की जरूरत है। पहलगाम हमले ने पीओके (पाक-अधिकृत कश्मीर) के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है।

पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकी गतिविधियों का केंद्र पीओके ही है। यह वही क्षेत्र है जहां आतंकी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं और जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। जबतक भारत के पीओके पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, आतंकवाद की समस्या का समाधान संभव नहीं है। देशवासियों का आक्रोश सामरिक दृष्टिकोण से जरूरी है। भारत ने पाक के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द कर और सभी तरह के राजनयिक सम्बन्धों को समाप्त कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पहलगाम हमला भारत के लिए एक चेतावनी है। इस घटना का जवाब देने के लिए हमें बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले आतंकियों और उनके आकाओं को बड़ा संदेश देना होगा। सैन्य कार-'वाई के साथ खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा। ताकि ऐसी घटनाओं को पहले ही रोका जा सके।

आतंकियों ने दी भारत को सीधी चुनौती

कश्मीर में फरवरी-2019 के बाद (पुलवामा आतंकी हमले के बाद) यह सबसे बड़ा और भीषण है। पुलवामा में 40 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को आतंकियों ने शहीद कर दिया था। पहलगाम में धार्मिक आधार पर चिन्हित कर पर्यटकों पर पहली बार आतंकी हमला किया गया है। इसपर संहार ने मार्च 2000 के चित्ती सिंह पुरा आतंकी हमले की याद ताजा करा दी जिसने 35 ग्रामीण सिक्खों को उनके घरों से बाहर निकाल कर मार दिया गया था। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति-बिल क्लिंटन कश्मीर प्रवास पर ही थे। इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति बेंस भारत के प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सऊदी अरब गए हुए थे। फिलहाल उन्हें तुरंत लौटना पड़ा। लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह को फोन पर निर्देश दिए कि तुरंत श्रीनगर जाएं और हालात तथा सुरक्षा का जायजा लें। घटना के बाद सरकार और सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गए हैं।

कश्मीर के पहलगाम जिले के बैसरन घसियाले मैदान में हुए मुस्लिम आतंकी हमले में धर्म पूछ कर गैर-मुस्लिमों को चुन-चुन कर हत्या की गई। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा जो कलमा नहीं सुना पाए उन्हें गोली मार दी। हिंदुओं को इस कल्ले आम को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। बताया गया है कि-आतंकी आतंकी थे। उन्होंने 50-70 राउंड गोली मारी और 29 सैलानियों को मौत की नींद सुला दिया। अधिकतर पुरुष पर्यटकों को ही निशाना बनाया गया। कर्नाटक की एक महिला ने पति की मौत के बाद कहा कि उसे भी मार दें तो आतंकियों ने जबाब दिया नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम जाओ जाकर मोदी को बता दो। इस जवाब से ही आतंकियों की सोच और मंशा समझी जा सकती है। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि ये इस्लामी आतंकशि है। आतंकी हमले के तुरंत बाद से देश भर में कथित- सेकुलर-लिबरल गैंग एक्टिव हो गया है। देश के कुछ पेड पक्षकार भी ये साबित करने लग गये हैं कि ये इस्लामी अटैक नहीं था। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की यूनिट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इंटेलिजेंस का दावा है कि - टीआरएफ आतंकी सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टर माइंड है। वह सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। सैफुल्लाह लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी -चीफ, है। उसे लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) के रावल कोट का रहने वाला है। वहीं से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को आपरेट कर रहा था। उसने मार्च में एक भाषण दिया था, जिस-ाका वीडियो सामने आया है इसमें बह सख्त लहजे में पाकिस्तान सरकार से कशमीर मुद्दा शांत न पड़ने देने की बात कह रहा है। सैफुल्लाह का ये भाषण मार्च-2025 का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तारीख और लोकेशन का पता नहीं है। पाकिस्तान को महसूस हो गया था कि - पर्यटकों की बढ़ती संख्या जो साल के अंत तक तीन करोड़ को पार कर सकती है। थी। उसको दुष्प्रचार नीति और कश्मीर को लेकर रचाई गई झूठी कहानी को नकार रही है। पाकिस्तान के लिए यह दोहरी पराजय थी। एक तो यह कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के निर्णय को कश्मीरी लोग धीरे-धीरे स्वीकार कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान ने यह सपना से जो रखा था कि वे इस फैसले के खिलाफ विद्रोह करेंगे। पाकिस्तान को इस बात से गहरी -चोट पहुंची है कि चीन और तुर्की को छोड़कर कोई भी देश उसके पक्ष में नहीं आया। यहां तक कि इस्लामी देशों ने भी भारत के निर्णय का समर्थन किया। दूसरे, पाकिस्तान को कश्मीर घाटी में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और देश के साथ बढ़ती एक जुटता से परेशान थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर में 60-70 आतंकवादी सक्रिय हो या सीमापार से घुस बैठ करके आते हों, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संघटन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकी हमला कर सकता है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी वैद इसे पुलवामा जैसा हमला ही मानते हैं। उनका मानना है कि- आतंकियों ने इलाकों के होटलों की रेकी कई बार की होगी और हमले को राजनीति खूब सोच समझ कर बनाई होगी। तभी वे इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहे और हमारे सुरक्षा तथा खुफिया क्षेत्र को भनक तक नहीं लगी। आतंकियों के पास अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी है। वे उन्हें कैसे मिले। आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार सख्त और गंभीर है। पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तन को सबक सिखाने के लिए भारत ने पांच बड़े फैसले लिए हैं। पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार आतंकियों की जन्म एवं शरण स्थलो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जिसकी मिसाल आने वाले समय दी जाएगी।

बृजलोक अकादमी के सेवा कार्य निरंतर संपन्न




आगरा । बृजलोक अकादमी ट्रस्ट द्वारा गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 101 घरेलू स्टील के बर्तन उपहार स्वरूप भेंट किए जा रहे हैं । संस्था द्वारा यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से अनवरत किया जा रहा है । संस्था समय-समय पर तमाम सामाजिक कार्यों को जनहित में संपन्न कराती रहती है । वहीं साहित्य, कला, संस्कृति की सेवा में भी कार्यक्रमों का आयोजन, प्रतिभा खोज, सम्मान समारोह, सत साहित्य प्रकाशन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों को मूर्ति रूप दिया जा रहा है । संस्था अध्यक्ष मुकेश कुमार ऋषिवर्मा बताते हैं कि संस्था को कोई बाहरी सहयोग प्राप्त नहीं होता । आर्थिक सहयोग संस्था के पदाधिकारी व सदस्य मिलकर ही करते हैं । ग्रामीण क्षेत्र में संस्था संचालित करना बहुत कठिन है । बगैर धन के संस्था को जीवित रखना बहुत कठिन कार्य है । संस्था के माध्यम से बड़े-बड़े कार्य तो नहीं हो पा रहे परंतु लघु कार्य नियमित हो रहे हैं । भविष्य में ईश्वर कृपा से व भामाशाहों के सहयोग से संस्था नये कीर्तिमान स्थापित करेगी ऐसा विश्वास है ।

पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी भी तप रही

मीडिया के दबाव या जनेच्छाओं से लड़ाइयां नहीं लड़ी जानी चाहिए। लेकिन जब पानी नाक तक-चढ़ जाए तो फिर हाथ-पैर चलाने ही पड़ते हैं। यह समय सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होने का है। पहलगाम में जान गंवाने वालों को इससे बेहतर कोई और श्रद्धांजलि नहीं होगी।

पुलवामा की घटना को 6 वर्ष हो चुके हैं। इस दरम्यान दुनिया और उसके तौर तरी को में जमीन-आसमान का फर्क आ चुका है। यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई और इजरायल के गाजा सैन्य अभियान ने विश्व राजनय के नये सिद्धांतों की परिभाषाएं रच दी। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बेहद दबाव के बावजूद न पुतिन झुके और न ही नेतन्याहू। उनको फौजें आज भी अपने दुश्मनों का सफाया करने में जुटी हैं।

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड और कनाडा को हथियाने का दंभ खुल्लम खुल्ला भरते हैं क्या भारत ऐसा कर सकेगा। इस पर कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं।

कहा तो बस इतना ही जा सकता है कि-पाकिस्तानी परमाणु बम और उसके दुरुपयोग की धमकियां मोदी की राह नहीं रोक सकतीं। वह पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के जरिए इसकी मुनादी कर चुके हैं। दुनिया के अन्य देश पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी से आजिज आ चुके है। यह अकारण नहीं कि-पहलगाम नर संहार के बाद विश्व के सभी प्रमुख देशों ने भारतीयों के साथ के साथ एकजुटता दिखाई है जिसका बदली हुई परिस्थितियों के साथ बेहतरीन सदुपयोग किया जा सकता है। देश के अंदर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हुए एकजुटता दिखाई है।

मीडिया के दबाव या जनेच्छाओं से लड़ाइयां नहीं लड़ी जानी चाहिए। लेकिन जब पानी नाक तक-चढ़ जाए तो फिर हाथ-पैर चलाने ही पड़ते हैं। यह समय सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होने का है। पहलगाम में जान गंवाने वालों को इससे बेहतर कोई और श्रद्धांजलि नहीं होगी। पहलगाम में हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, देश के दुश्मनों में भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जब ये शब्द मधुबनी की धरती पर बोल रहे थे, तब उनके चेहरे पर गुस्से की गहन छाया साफ देखी जा सकती थी। यह पहला मौका था कि जब किसी सार्वजनिक सभा में ऐसे कठोर शब्द कहे थे। ये ताकतवर वाक्य उन लोगों के जख्मों पर मरहम की तरह थे जिन्होंने अपने घर के लोग खोए थे। ये अल्फाज आहत देशवासियों को भी भरोसा दिला रहे थे कि हम सिर्फ कूटनीतिक कार्रवाई तक नहीं रुकेंगे। मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है लेकिन लेकिन इतना तय है कि जो होगा वह अप्रत्याशित और अकल्पनीय होगा। भरोसा न हो तो 15 फरवरी 2019 को ओर लौटें। समूचा देश उस समय पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से आहत था। उस दिन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि आतंक के दोषियों और उन्हें मदद देने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। पाकिस्तान इस भ्रम में न रहे कि वह भारत को अस्थिर कर सकता है। पाकिस्तान सहित कुछ सियासत इसे महज चुनावी भाषण मानने की भूल कर बैठे थे। अगले दस दिन जो बालाकोट में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने अद्भुत रूप से देखा। इससे पहले भारत आतंकवाद से आहत होने के बाद बस गाल बनाकर रह जाता था। इस बार हमारी वायु सेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर निर्धारित ऑपरेशन को अंजाम दिया। बल्कि सरकार ने उसे दुनिया को यह बताने और जताने में कोई संकोच नहीं किया था। यह भारतीय रणनीतिक बदलाव का सार्थक लम्हा था। तय हो गया था कि अब भारत भूमि को रक्त स्नान कराने वाले कहीं भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, जरूरी हुआ तो सीमा पार करने में भी नहीं हिचकेंगे।

बहस : न्याय पालिका और कार्य पालिका के बीच हो लक्ष्मण रेखा

23 गई 1949 को नजीरुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वह एक बात जो स्वतंत्रता को ठोस आधार दे सकती है। वह है जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास । अगर विश्वास नहीं है तो सरकार की स्थिरता समाप्त हो जाएगी। अतः न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, बल्कि उसकी गारंटी दो जाए। अगले दिन अनंतशयनम्‍ आयंगर ने स्मरण कराया कि उच्चतम न्यायालय लोकतंत्र प्रहरी और संरक्षक है, इसलिए उसके कार्य में कार्यपालिका का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए उनकी नियुक्ति वेतन और कार्यकाल जैसे विषयों में कार्यपालिका का बहुत कम अथवा बिल्कुल ही संबंध नरहे।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सभी मुमकिन है जब न्यायाधीश सभी प्रकार के दबावों और प्रलोभन से मुक्त हो। यह कैसे संभव है हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था में नियुक्ति के स्वतः सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर संविधान सभा क्या सोचती है। यह जानना चाहिए। शिब्बन लाल सक्सेना का सुझाव था कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश की नियुक्ति को दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पुष्टि अनिवार्य की जाए। इससे लाभ होगा कि- कार्यपालिका के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मान्यता होगी लेकिन नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप पर नियंत्रण के लिए दोनों सदनों का दो तिहाई प्रभावी भूमिका में रहेगा। के. टी. शाह का मत था कि- न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति न केवल न्यायपालिका से परामर्श लें बल्कि राज्य परिषद को भी परामर्श में शामिल करें। ताकि दलबंदी और राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि के लिए दोनों सदनों के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के समर्थन को रोहिनी कुमार चौधरी ने खतरनाक सिद्धांत बताते हुए उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत न्यायाधीशों की नियुक्ति में बहुसंख्यक दल के वर्चस्व को स्थापित कर मनचाही नियुक्तियों को आसान करेगा। चौधरी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यों के उच्च न्यायालय से भी परामर्श का विरोध किया था। उनके अनुसार, उच्च पद की नियुक्ति के लिए नीचे के पद पर आसीन व्यक्ति से परामर्श का क्या औचित्य हो सकता है ?इस विषय पर अनंतशयनम आयंगर का सुझाव था कि- उच्चतम न्यायालय में-यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से परामर्श को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा जाए। डॉ. भीम राव आंबेडकर ने नियुक्ति प्रक्रिया के संबंधों आए सुझावों, संशोधनों के संबंध में कहा था कि यह तीन दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। एक- उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। दूसरा-राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत की स्वीकृति हो और तीसरा-राज्य परिषद से सहमति लेकर राष्ट्रपति नियुक्तियां करें। उक्त सुझावों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आंबेडकर ने खारिज किया। कुछ अन्य देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियां सीनेट की सहमति से होती हैं लेकिन भारत में अभी उत्तर दायित्व की इतनी भावना नही उत्पन्न हो सकी है. इसलिए इसमें दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार की सभी नियुक्तियों के लिए दोनों सदनों की सहमति पाना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मध्यगमार्ग का अनुसरण किया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम और अंतिम प्राधिकारी नहीं है और न ही विधान मंडल का उसमें प्रभाव है। अतः ऐसे लोगों से परामर्श का प्रावधान किया गया है जो उचित परामर्श दे सके। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाना अनिवार्य है लेकिन न्यायाधीश में भी साधारण मनुष्य की कमजोरी भावनाएं होंगी। अतः मुख्य न्यायाधीश के मत को मानने का यह अर्थ होगा कि उसे वह अधिकार दिया जा रहा है जो न राष्ट्रपति को दिया जा रहा है और न सरकार को । इसलिए न्यायाधीश का परामर्श बाधा सूचक नहीं रखा जा सकता। न्यायाधीश, प्रलोभन मुक्त रहकर न्याय सुनिश्चित कर सकें।

इस विषय पर के.टी. शाहने संशोधन प्रस्तुत किया था। शाह के अनुसार- न्यायाधीश किसी प्रलोभन में न पड़े, इसके लिए उनको कार्यपालिका और विधानमंडल से कोई संपर्क न होना जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि पद पर रहने या सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश को कार्यपालिका के किसी पद पर किसी पद पर पाबंदी की संविधान में व्यवस्था की जाए, हालांकि पद त्याग की स्थिति में उन्हें अन्य नागरिकों के समान अधिकारों का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन मोहम्मद ताहिर ने-न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी किसी अ-लाभकारी पद के लिए राष्ट्रपति की स्पष्ट अनुमति अनिवार्य करने की मांग की थी।

न्यायाधीशों की आयु सीमा पर भी विचार आए थे। विश्वनाथ दास ने इसे 65 से 60 वर्ष करने की मांग की थी, तो दूसरी ओर आयंगर ने इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 70 वर्ष और कनाडा में 75 वर्ष का जिक्र करते हुए भारत में इसे 70 वर्ष निश्चित करने की मांग की थी। इस विषय पर पंडित नेहरू ने कहा था कि सर्वोच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति विषय पर युवकों को आजीविका का अवसर देने के नजरिए से विचार नहीं किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश के किसी पद ग्रहण के प्रस्ताव का डा. आंबेडकर ने विरोध किया था।उनका कहना था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पद ग्रहण की स्थिति में अंतर है।

लोक सेवा आयोग सरकार की सेवा करता है इसलिए कार्यपालिका से उसका संबंध है लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक है। साथ ही न्याय संबंधी योग्यता रखने वालों को कुछ कामों में लगाना आवश्यक होता है। अतः न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति के पश्चात वकालत के अलावा किसी अन्य पद के लिए उन्हें निषिद्ध किया जाना अनावश्यक है।

विनम्र श्रद्धांजलि

पहलगाम में गत दिनों हुए पर्यटकों को प्राणघातक हमले के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति घूँघट की बगावत परिवार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं दुःख की इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करते हुए उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे तथा परिजनों को दु;ख को सहन करने की शक्ति त्रदान करें।

घूँघट की बगावत परिवार

मुंशी प्रेमचन्द कृत नाटक रंगीले बाबू का मचन हुआ

प्रयागराज। मुंशी प्रेमचन्द कृत नाटक रंगीले बाबू का मंचन हुआ निर्देशन अनुपमा साहू तथा नाट्य रूपांतरण सचिन चन्द्रा ने किया द स्टेज फाउंडेशन के सौजन्य से नाटक में दिखाया गया कि बाबू रसिक लाल के हालत देखते देखते ऐसे बदले कि कुछ समय में ही वह शहर के रईसों में उनकी गिनती होने लगी बाबू रसिक लाल जीवन को जीने पर विश्वास करते थे न कि जीवन को काटने पर। रसिक लाल के बच्चे

अब बड़े हो गये तो कुछ समय में ही उनकी बड़ी बेटी का विवाह हो जाता है और अचानक उनके दामाद का देहान्त हो जाता है परन्तु रसिक बाबू का जीने का अन्दाज वही था फिर कुछ साल के बाद पुत्र का भी विवाह तय हो गया और विवाह वाले दिन बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी चल रही थी कि अचानक सब कुछ मातम में बदल जाता है क्योंकि ठीक उसी समय

उसके पुत्र का आकस्मिक निधन हो जाता है तो लोगों मे बड़ा कौतूहल का विषय होता है कि अब क्या होगा उधर बाबू रसिक लाल सभी से कहते हैं कि आज मेरे इकलौते पुत्र का विवाह है देखी कोई कमी न होन पाये और ठीक उसी समय मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखते हुए जैसे कह रहे हो और भी कुछ बचा-हो तो कर लो लेकिन मेरा अन्दाज वही रहेगा । मुख्य किरदार में मंच पर चंकी बच्चन, आर्यन नागर . गोपाल कुशवाहा . सुशान्त शुक्ला . शिखर . प्रिंस पाण्डे तथा मंच परे अवनीश मिश्रा मोहम्मद आबिद तथा अनुज इत्यादि रहे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादकः पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com